सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 111, नई दिल्ली, सोमवार 30 जून 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

अगर मेहनत को आदत बना लिया जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है।

03 राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 से नवाजे गए डॉ डीसी प्रजापति।

06 भारतीय शिक्षा में पुनर्विचार भाषा

08 शेखावाटी के संतों के सानिध्य में हैदराबाद में होगी भजन संध्या

आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नेतृत्व में सम्पन्न हुई व्यवसायिक वाहन मालिकों की बैठक

संजय बाटला

- बैठक का मुख्य मुद्दा सीएक्यूएम के बीएस-4 और उससे नीचे के मानकों के गइस वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की परजोर मांग।
- क्या थी मुख्य मांग और फैसला दिल्ली एन सी आर के परिवहन व्यवसायी हुए लामबंद मांगें पूरी न होने पर बंद करेंगें अपनी परिवहन सेवाएं

नई दिल्ली। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (ए आई एम टी सी) भारत के सड़क परिवहन क्षेत्र के माल एवं यात्री दोनों कों के हितों की रक्षा हेतु वर्ष 1936 से कार्यरत एक शीर्ष संस्था है।ए आई एम टी सी लगभग 95 लाख ट्रक बालकों और लगभग 26 लाख नित्री बस, टैक्सी एवं मैक्सी-कैथ संचालकों का प्रतिनिधित्व करती है, जो देशभर में फैली लगभग 3500 तालुका, जिला एवं राज्य स्तरीय परिवहन संघों एवं यूनियनों की शीर्ष इकाई हैं।

आज पंजाची बाग क्लब, विल्ली में ट्रांसपोर्ट समुदाय की एकता और संख्या बल का एक प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को मिला। पिछले कुछ समय से दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम (सी. ए. क्यू. एम, द्वारा दिल्ली में बीएस-4 और उससे नीचे के मानकों वाले गुइस वाहनों के। नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर परिवहन व्यवसायियों में गहरा रोष व्याप्त है।

26 जून को इसी संदर्भ में दिल्ली-एनसीआर की ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के हर वर्ग जैसे, टुक, ट्रांसपोर्ट, टेम्पो, ऑटो, टैक्सी, बस, ड्राइवरस, से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं, संगठन एवं यूनियंस, डॉ. हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेत्राय में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कॉग्रेस (ए आई एम टी. सी) के बैनर तले एकत्रित हुई और यह निर्णय लिया कि सरकार के इस तुगलकी फरमान के खिलाफ पूरे बल और एकता के साथ विरोध किया जाएगा।

आज की बैठक में दिल्ली-एनसीआर के सभी प्रमुख संगठनों के प्रतिनिधि एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने इस गंभीर विषय पर अपने विचार व्यक्त किए और आगे की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। इस मुहिम में न केवल ट्रक चालकों ने, बल्कि ऑटो, टैक्सी, रिक्शा, टेंपो, बस चालकों और ड्राइवर यूनियनों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया। लगभग 65 से अधिक परिवहन से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि और 600 से ज्यादा सदस्य इस सभा में शामिल हो।

डी हरीश सभरवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ने कहा कि यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं, बल्कि लाखों ट्रांसपोर्ट साथियों की आजीविका की रक्षा की लड़ाई है। अगर सरकार ने इन मांगों को गंभीरता से नहीं लिया, तो आने वाले समय में आंदोलन को और तेज किया जाएगा और संपूर्ण ट्रांसपोर्ट समुदाय स्वेच्छा से अपना कार्य बंद कर देगा।"

उन्होंने कहा कि सीएक्यूएम का यह आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय के भी विरुद्ध है, जिसमें स्पष्ट रूप से बीएस-4 वाहनों को दिल्ली-एनसीआर में 10 वर्षों तक संचालन की अनुमति दी गई है। वेशभर के हजारों छोटे व मध्यम श्रेणी के परिवहन उद्यमियों ने सरकार की पूर्व

घोषित नीति पर भरोसा कर बीएम-4 ट्रकों में भारी निवेश किया था। इन वाहनों के पास वैध परमिट, फिटनेस प्रमाण-पत्र और पीयूसीसी उपलब्ध हैं। ऐसे में यह अचानक लगाया गया प्रतिबंध सैकड़ों वाहन स्वामियों की आजीविका पर संकट खड़ा करेगा, बैंकों की किश्तें चुकाने में असमर्थता होगी, और दिल्ली की आम जनता तथा व्यापारियों को भी भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकार के समक्ष एक सांझा मांग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें तीन मुख्य चिंदुओं को चिन्हित किया गया है:

दिल्ली में बीएस 4 च नीचे के मास्कों के गुड्द्र वाहनों पर 1 नक्चर 2025 से घोषित प्रतिबंध के आदेश को सी. ए. क्यू. एम. सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए

एप आधारित ओला, उबर व मोटर बाइक टैक्सी जैसे गैर कानूनी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए

सरकार ड्राइवरस कल्याण बोर्ड के गठन का वादा पूरा करे।

साथ ही यह भी पोषणा की गई कि यदि सरकार 1 नवम्बर 2025 में दिल्ली में बीएस-4 और उससे नीचे के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू करती है, तो विरोध स्वरूप केवल टुक ही नहीं, बल्कि बीएस-6, सीएनजी एवं इलेक्ट्रिक वाहन भी दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे। इससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होगी, स्कूल बसों सहित

सार्वजनिक आवागमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परिणामस्वरूप दिल्ली की आम जनता और व्यापारिक वर्ग को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण

जिम्मेदारी दिल्ली सरकार और सीएक्यूएम की होगी।

हम आपसे विनम्न अनुरोध करते हैं कि आप अपनी सम्मानित मीडिया के माध्यम से इस उभरती हुई गंभीर स्थिति को उजागर करें और सरकार को सतर्क करें कि सौएक्यूएम के इस निर्णय के क्या संभावित दूरगामी दुष्परिणाम हो सकते हैं।

दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने आल इंडिया मोटर्स कांग्रेस की मीटिंग में शामिल नहीं हुए

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है की हमारे सारे मेंबर्स आल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी, टेम्पो ट्रैवेलर और टूरिस्ट बसों के व्यवसाय से जुड़े है. जो आज की मीटिंग थी वो 1 नवम्बर 2025 से CAQM द्वारा डीजल BS 4 के टेम्पो ट्रक के बंद करने के खिलाफ थी.

संजय सम्राट का कहना है की हमारे ट्रांसपोर्टर्स ने 2020 तक डीजल BS 4 की टैक्सी बसें खरीदी और 2020 में करोना महामारी आ गई, 2 सालो तक हमारी टैक्सी बसें पार्किंग में खड़ी रही. अपनी जेब से लोगो ने गाड़ियों की किस्तें भरी, जो किस्तें नहीं भर पाए उनकी टैक्सी बसें बैंक और प्राइवेट फाइनेंसर वाले घरों से उठाकर ले गए. बड़ी मुश्किल से ट्रांसपोर्टर्स ने कर्जा लेकर दोबारा से अपना बिज़नेस जमाया. लेकिन फिर कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी घटना और फिर पाकिस्तान से युद्ध की वजह से सारा काम धंधा बंद हो गया. और ऊपर से अब हमारी टूरिस्ट डीजल BS 4 बसों को 1 नवम्बर 2026 से बंद करने का फरमान भी CAQM ने दिया है. जिसकी वजह से भारत का ट्रांसपोर्टर्स आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान हो गया है.

संजय सम्राट का कहना है इसलिए हमने CAQM की शिकायत 26 जून 2025 को दिल्ली की मुख्यमंत्री से की और

अपनी समस्याओ से अवगत कराया.दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने हमारी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन को अस्वासन दिया है की हमारी मांगो पर गौर करके हमारी समस्याओ का समाधान करेंगी.

संजय सम्राट का कहना है आज तक टूरिस्ट टैक्सी बसों वालो ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है. जब हमारी डीजल टूरिस्ट टैक्सी, टेम्पो ट्रेवलर और बसें सरकार बंद करी रही थी तो हमारी एसोसिएशन ने मोर्चा सम्हाला और लगातार हमने प्रदर्शन किये. और दिल्ली की भूतपूर्व तानाशाही सरकार के खिलाफ दिल्ली के रोड तक जाम किये. औरअपने ट्रांसपोर्टरस को उनका हक़ दिलवाया.

जब कमिसन फॉर एयर क्वालिटी मेनेजमेंट(CAQM)ने हमारी टूरिस्ट डीजल BS 4 बसों को 1 नवम्बर 2023 में बंद कराया तो हमारी ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में जंतर मंतर पर भारी धरना प्रदर्शन CAQM और भूतपूर्व दिल्ली सरकार के खिलाफ किया गया और CAQM और भूत्तपूर्व दिल्ली सरकार ने हमारी डीजल BS 4 टूरिस्ट बसों को चलने की इज्जाजत दें दी.

दिल्ली में BS 6 डीजल बसों के रजिस्ट्रेशन खोलने के लिए भी हमारी एसोसिएशन ने धरने प्रदर्शन किये. और भूतपूर्व दिल्ली सरकार से डीजल बसों के रजिस्ट्रेशन को खुलवाया.

संजय सम्राट का कहना है आज की मीटिंग डीजल के टेम्पो ट्रक वालो की थी, इन टेम्पो ट्रको की एसोसिएशन ने कभी भी टूरिस्ट टैक्सी बसों वालो का साथ नहीं दिया. इसलिए डीजल के टेम्पो ट्रक बंद होने का बेशक हमें दुख है लेकिन उनकी लड़ाई में हमारी टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन शामिल नहीं होंगी.

संजय सम्राट का कहना आज तक हमने अपने टूरिस्ट टैक्सी बसों वालो की लड़ाई खुद लड़ी है और हम खुद सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए.अगर CAQM या दिल्ली/केंद्र/राज्य सरकार ने हमारी डीजल टैक्सी बसों की जितनी लाइफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मे है उतनी नहीं दी तो हम बड़ा आंदोलन CAQM,दिल्ली/राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ करेंगे.

संजय सम्राट का कहना है की वो दिल्ली के टूरिस्ट टैक्सी- बसों, और टेम्पो ट्रेवलर वालो के लिए बहुत सालो से काम कर रहे है और 24 घंटे उनके फोन उठाते है और उनकी समस्याओ का समाधान करते है इसलिय दिल्ली एनसीआर के ट्रांसपोर्टर्स का हम पर भरोसा है.

इसलिए इस बार भी हम अपना हक़ लेकर रहेंगे. जितनी गाडी की लाइफ उतनी उसको रोड पर चलवाएंगे.

संजय सम्राट, अध्यक्ष
दिल्ली टैक्सी एन्ड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन.

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

क्या दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम और परिवहन विभाग का अधिकृत 'लॉगो' अपने निजी आइडेंटीफिकेशन कॉर्ड पर प्राइवेट व्यक्ति प्रयोग कर सकता है ? तीनों विभागो से जनता का सवाल

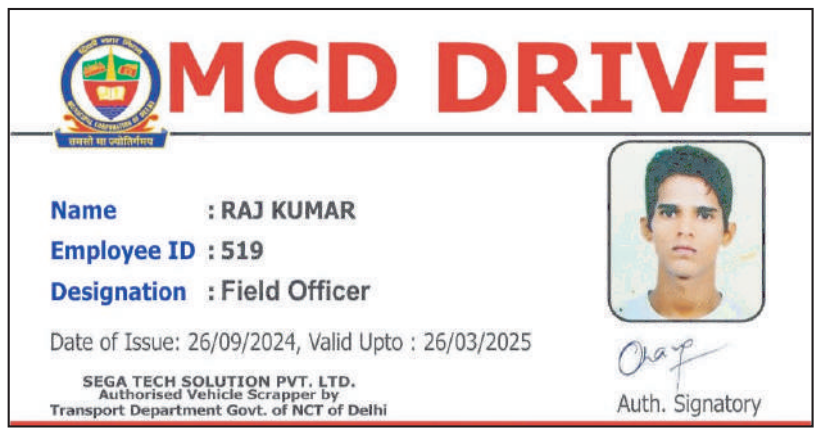

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली में भारत देश की जनता के समाय सीमा पूरे कर चुके वाहनों और गैर कानूनी ढंग से चल रहे वाहनों को जब्त कर स्क्रैप करवाने के लिए बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को अपने साथ जोड़ा और साथ ही अपने पद के बल का दुरूपयोग करते हैं दिल्ली पुलिस और अन्य नगर निगम को पत्र लिखा कर उन्हीं बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को जोड़ने के लिए प्रभावित किया। यह वो स्क्रैप डीलर से जिन्होंने सरकारी विभागों की ताकत का दुरूपयोग करते हुए वाहन तो प्राप्त कर लिए पर उनके बदले वाहन मालिकों या सरकारी विभाग में को उस वाहन का मिनिमम स्क्रैप मुल्य निर्धारित है वह भी ना तो वाहन मालिकों को दिए और ना ही सरकारी विभाग में जमा करवाए। इसके अलावा इन में से अधिकतर वाहन स्क्रैप में ने वाहनों को स्क्रैप किए बिना ही भारत सरकार और राज्य सरकारों को अरबों रुपए का चूना अलग से लगवा दिया।

आपकी जानकारी हेतु बता दें इन स्क्रैप डीलरो ने अपने द्वारा सड़को पर छोड़े हुए कर्मचारियों को जो आइडेंटीफिकेशन कॉर्ड जारी किए हुए हैं उन्हें देख कर कोई भी व्यक्ति उन्हें विभाग का कर्मचारी ही समझेगा ना की एक प्राइवेट व्यक्ति, और यह वो व्यक्ति हैं जो आम आदमी से ना तो बदतमीजी करने से डरते हैं और ना ही हाथापाई यानी पूर्ण गुंडागर्दी। इस बात के अनेकों सबूत उपलब्ध हैं और अनेकों वीडियो भी उपलब्ध है। *कल ही बुराड़ी पुलिस स्टेशन में एक एफ.आई.आर. और दर्ज हुई है जिसके बाद पता चला की चलता हुआ वाहन बलपूर्वक रुकवा कर ड्राइवर को बुरी तरह पीट कर छीन कर ले गए और बाद में जब लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और पीटा तो उसको स्क्रैप डीलर को सुपुर्द करने की बात कही जब की उस समय उनके साथ सरकारी विभाग का कोई भी अधिकारी उपलब्ध नहीं था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में लुट और पकड़े जाने पर बुराड़ी थाने में शिकायत एफ.आई.आर. दर्ज हुई है। दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा निजी रूप से जोड़े गए स्क्रैप डीलरो के द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के पास पाए जा रहे हैं ऐसे प्रमाण पत्र (Identity Card) रख कर सड़को पर लुट मचाने और मचवाने का जिम्मेदार कौन? और कौन लेगा यह जिम्मेदारी बड़ा सवाल।

रहस्यमयी नागद्वारी यात्रा 2025: सावन में खुलता है नागलोक का द्वार, जानिए पूरी जानकारी और धार्मिक महत्व

सतपुड़ा एक्सप्रेस पचमढ़ी (मध्य प्रदेश):सतपुड़ा की घनी वादियों और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित नागद्वारी यात्रा एक रहस्यमयी और अत्यंत श्रद्धास्पद धार्मिक यात्रा है, जो सिर्फ साल में एक बार नागपंचमी के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए खोली जाती है। यह यात्रा मध्यप्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में स्थित है।—

नागद्वारी यात्रा की विशेषताएं यात्रा अवधिः इस वर्ष नागद्वारी यात्रा 19 जुलाई 2025 से शुरू हुई है, जो 10 दिन तक चलेगी।

स्थानः जलगली से 12 किमी की पहाड़ी पदयात्रा, जो कठिन और चुनौतीपूर्ण है।अनुमतिः सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र होने के कारण साल में सिर्फ एक बार इस मार्ग पर प्रवेश की अनुमति होती है।—

नागलोक तक का रहस्यमयी रास्ता श्रद्धालुओं को नागद्वार तक पहुंचने के लिए घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और फिसलन भरे पगडंडियों से गुजरना पड़ता है। यह मार्ग सीधा नागलोक की ओर जाने वाला माना जाता है। यात्रा में श्रद्धालुओं का सामना कई बार जहरीले सांपों से होता है, लेकिन मान्यता है कि यह सांप भक्तों को नुकसान नहीं पहुंचाते।—

नागदेव की गुफाएं और मूर्तियां

चिंतामणि गुफाः लगभग 100 फीट लंबी गुफा, जिसमें

नागदेव की मूर्तियां स्थापित हैं।

स्वर्ग द्वारः चिंतामणि गुफा से 500 मीटर दूर एक और पवित्र गुफा, जहां नागदेव की उपस्थिति मानी जाती है।

मुख्य मंदिर गुफाः 35 फीट लंबी गुफा जहां श्रद्धालु दर्शन करते हैं।

अमरनाथ जैसी ही नागद्वारी की यात्रा जैसे बाबा अमरनाथ यात्रा हिमालय की ऊंचाइयों से होकर गुजरती है, वैसे ही नागद्वारी यात्रा सतपुड़ा की सर्पाकार पगडंडियों से होकर पूरी होती है। दोनों ही यात्राएं भक्तों के लिए कठिन लेकिन धर्म और प्रकृति के अद्भुत संगम की अनुभूति कराती हैं।—

मान्यताएं और धार्मिक महत्व

कालसर्प दोष निवारणः नागद्वारी यात्रा को कालसर्प दोष से मुक्ति दिलाने वाली यात्रा माना जाता है।

शिवलिंग पर काजल चढ़ानाः गोविंदगिरी पहाड़ी की गुफा में स्थित शिवलिंग पर काजल लगाने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।

आस्था की परीक्षाः दो-दो पीढ़ियों से लोग यह यात्रा कर रहे हैं; यह यात्रा धैर्य, भक्ति और आत्मशक्ति की परीक्षा मानी जाती है।

यात्रा मार्ग और तैयारी जलगली से लेकर मुख्य गुफा तक कुल 12 किमी की पैदल यात्रा।मार्ग में 01 से 18 तक के दर्शन स्थल चिन्हित हैं जिन्हें एक ही दिन में कवर किया जा सकता है।शारीरिक क्षमता और मौसम को ध्यान में रखते हुए ही यात्रा पर निकलें।

नागद्वारी यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो प्रकृति की गोद में, आस्था के साथ जुड़कर मन, शरीर और आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देता है। यह यात्रा उन श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत वरदान है जो आस्था की राह पर जोखिम उठाकर दिव्यता की अनुभूति करना चाहते हैं।

कैलाश मंदिर एलोराः रहस्य जो आज भी है अनसुलझा

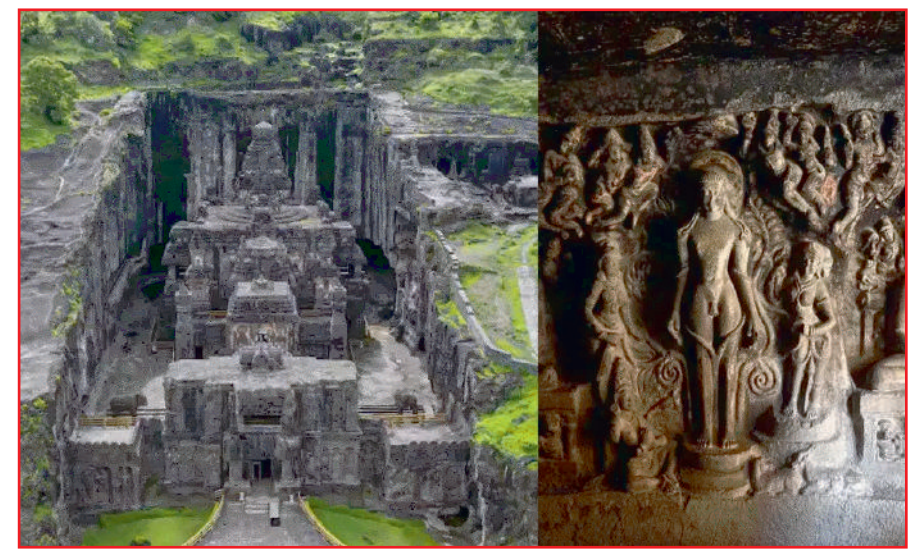

महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर (Cave 16) को देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। यह मंदिर न केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जिसे आज तक कोई पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है।

एक ही पत्थर से बना पूरा मंदिर !

कैलाश मंदिर को किसी ईंट या जोड़ से नहीं बनाया गया है, बल्कि एक ही विशालकाय चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर तराशा गया है। यह प्रक्रिया अपने आप में दुनिया की किसी भी प्राचीन स्थापत्य शैली से अलग है।

कैसे हुआ यह संभव?

यह सवाल आज भी अनुत्तरित है

8वीं शताब्दी में, जब न कोई क्रेन थी, न डायनामाइट, तो आखिर इतने बड़े पत्थर कैसे हटाए गए?

इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। कुछ मानते हैं कि यह मानव श्रम और संकल्प की मिसाल है, जबकि कुछ इसे प्राचीन उच्च तकनीक या यहां तक कि एलियन इंटरवेंशन का उदाहरण मानते हैं।

आध्यात्मिक ऊर्जा और शक्ति

स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्थान में अलौकिक ऊर्जा है। ध्यान करने वाले साधक कहते हैं कि यहां बैठते ही मन एक अलग शांति की अवस्था में चला जाता है।

कई योगियों ने दावा किया है कि यह स्थान 'सिद्धों' की भूमि रही है, जहां अद्भुत शक्तियों का प्रयोग होता था।

एक और रहस्य

इतना विशाल और अद्भुत मंदिर कैसे बना, इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। न कोई शिलालेख, न कोई वर्णन, जो स्पष्ट रूप से बताता हो कि यह कार्य कब शुरू हुआ, कितने समय में पूरा हुआ और किसने किया।

हनुमान जी की कृपा पाने के लिए अपनाएं रोज़मर्रा के ये 5 आसान उपाय

हनुमान जी को संकटमोचन, अजेय शक्ति और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी उनके आशीर्वाद की प्राप्ति चाहते हैं, तो अपनी दिनचर्या में कुछ आसान आदतें शामिल कर सकते हैं। जानिए वो पाँच कार्य जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं:

1. रोज़ सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें हर दिन सुबह स्नान के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और डर व नकारात्मकता दूर होती है। यह अभ्यास आत्मबल और शांति प्रदान करता है।

2. ज़रूरतमंदों की सेवा करें हनुमान जी सेवा के प्रतीक हैं। रोज़ाना छोटे-छोटे सेवा कार्य जैसे बुज़ुर्गों की मदद, भोजन वितरण या किसी ज़रूरतमंद की सहायता करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है।

3. मंगलवार और शनिवार का व्रत रखें इन दोनों दिनों को हनुमान जी को समर्पित माना जाता है। व्रत रखकर और मंदिर में दीपक जलाकर भक्ति करने से मानसिक शक्ति और अनुशासन की प्राप्ति होती है।

4. लाल रंग और सिंदूर का प्रयोग करें हनुमान जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। मंदिर में सिंदूर अर्पित करना और लाल धागा या वस्त्र पहनना श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है।

5. बुरी संगत और नकारात्मकता से बचे हनुमान जी सच्चाई, भक्ति और सदाचार के प्रतीक हैं। इसलिए ग़लत संगत, झूठ और आलस्य से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है।

बदलते मौसम में बच्चे होने लगे हैं बीमार तो ट्राई करें ये घरेलू नुस्खे, जल्द मिलेगा आराम

आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाने से मामूली सर्दी-जुकाम या बुखार आसानी से इलाज किया जा सकता है। वहीं अगर यह लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

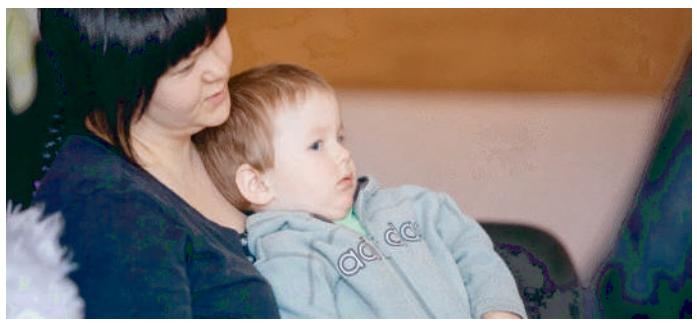

भारत के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसूम शुरू होने के साथ ही सर्दी-जुकाम, बुखार, खांसी और ठंड लगने जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। वहीं इस मौसम से बच्चे और बुजुर्ग थोड़ा जल्दी प्रभावित होते हैं। इसलिए इस मौसम में बच्चों और बुजुर्ग को स्वस्थ रखना कई बार एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाने से मामूली सर्दी-जुकाम या बुखार आसानी से इलाज किया जा सकता है। वहीं अगर यह लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

यहां जानिए सर्दी-जुकाम या बुखार का घरेलू इलाज

हल्दी वाला दूध

एक्सपर्ट के मुताबिक सर्दी-जुकाम या बुखार से राहत पाने के लिए बच्चों को हल्दी वाला दूध का सेवन बड़ा असरदार माना जाता है। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जोकि इंफेक्शन से लड़ने और गले की खराश में राहत देने का काम करते हैं। इसलिए सोने से पहले गुनगुने दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर बच्चे को पिला दें।

गुनगुना पानी

सर्दी-जुकाम या बुखार होने पर बच्चों को ठंडी चीजें नहीं देनी चाहिए। बल्कि बच्चे को पीने के लिए गुनगुना या हल्का गर्म पानी देना चाहिए। इससे गले की खराश और सूजन की समस्या कम हो सकती है।

अदरक, तुलसी और शहद का काढ़ा

गले की खराश, खांसी या बुखार आदि में आप बच्चे को तुलसी के पत्ते, अदरक, काली मिर्च और शहद का काढ़ा बनाकर दे सकते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद होता है। हालांकि एक साल से छोटे बच्चे को यह काढ़ा नहीं देना चाहिए।

तुलसी और अदरक का रस

तुलसी के पत्तों और अदरक का रस और थोड़े से शहद में मिलाकर देने से सर्दी-जुकाम और बुखार से राहत मिल सकती है।

तरल पदार्थ

अगर बच्चे को बुखार हो गया है, तो उसको पानी पिलाएं, नारियल पानी, सूप या ताजे फलों का रस भी दे सकते हैं। इससे शरीर में पानी की कमी भी पूरी होगी और एनर्जी भी बनी रहेगी।

बारिश के पानी से भी करें बच्चे का बचाव

बच्चे को बारिश में भीगने या गंदे पानी में खेलने से रोकें।

अगर बच्चा गीला हो गया है तो तुरंत उसके कपड़े बदल दें।

बच्चों की साफ-सफाई का खास ख्याल रखें।

पौष्टिक आहार दें, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत हो।

नींद पूरी करने और आराम करने के लिए पर्याप्त समय दें।

समय-समय पर टीकाकरण जरूर कराएं।

कांचीपुरम क्यों है हजारों मंदिरों का शहर? जानें इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व

कांचीपुरम हजारों मंदिरों का शहर है, ये कभी पल्लव राजवंश की राजधानी था, और 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच यहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रहा। इस शहर में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के मंदिर के अवशेष आज भी मौजूद हैं, जो इसकी धार्मिक विविधता और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं।

तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर कांचीपुरम, जिसे 'हजारों मंदिरों का शहर' कहा जाता है, भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह शहर सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए भी एक अद्भुत स्थल है।

प्रमुख मंदिर

यहाँ के प्रमुख मंदिरों में कैलाशनाथर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिसकी वास्तुकला पत्थर में उकेरे गए उत्कृष्ट चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एकाम्बरेश्वरर मंदिर में स्थित हजारों साल पुराना आम का पेड़ और भव्य गोपुरम श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। वहीं कामाक्षी अम्मन मंदिर, देवी शक्ति को समर्पित है और शक्ति पीठों में गिना जाता है।

रेशमी साड़ियों का घर

न केवल मंदिरों के लिए, बल्कि इसकी शानदार कांची सिल्क साड़ियों के लिए भी दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यहाँ की साड़ियाँ हाथ से बुनी जाती हैं और पारंपरिक विवाहों तथा त्योहारों में खास महत्व रखती हैं।

कैसे जाएँ

कांचीपुरम चेन्नई से लगभग 75 किलोमीटर दूर है और सड़क या रेल मार्ग से आसानी से पहुँचा जा सकता है। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक होता है।कुल मिलाकर, कांचीपुरम एक ऐसा स्थान है जहाँ आस्था, कला, संस्कृति और परंपरा एक साथ जीवंत रूप में दिखती हैं। अगर आप भारत की गहराई से पहचान करना चाहते हैं, तो कांचीपुरम की यात्रा ज़रूर करें।

शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और औपनिवेशिक विरासत का अनोखा मेल है कसौली

कसौली की स्थापना 1842 में ब्रिटिश राज के दौरान एक सैन्य छावनी के रूप में हुई थी। यहाँ आज भी कई ब्रिटिश-युग की इमारतें और चर्च मौजूद हैं, जो इसके इतिहास को जीवंत बनाए रखते हैं। साथ ही, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सुथरी जलवायु इसे एक बेहतरीन हिल स्टेशन बनाती है।

हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में स्थित कसौली एक छोटा लेकिन बेहद आकर्षक और शांत पहाड़ी स्थल है। समुद्र तल से लगभग 1,900 मीटर की ऊँचाई पर बसा कसौली अपनी हरियाली, शांत वातावरण, औपनिवेशिक इमारतों और मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह एक आदर्श स्थान है उन लोगों के लिए जो भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर कुछ सुकून के पल बिताना चाहते हैं।

कसौली का इतिहास और विशेषता

कसौली की स्थापना 1842 में ब्रिटिश राज के दौरान एक सैन्य छावनी के रूप में हुई थी। यहाँ आज भी कई ब्रिटिश-युग की इमारतें और चर्च मौजूद हैं, जो इसके इतिहास को जीवंत बनाए रखते हैं। साथ ही, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और साफ-सुथरी जलवायु इसे एक बेहतरीन हिल स्टेशन बनाती है।

प्रमुख आकर्षण

1. मंकी पॉइंट (Monkey Point)

कसौली का सबसे ऊँचा स्थान मंकी पॉइंट है, जहाँ से सतलुज नदी, चंडीगढ़ और शिमला के दृश्य साफ दिखाई देते हैं। यहाँ एक छोटा हनुमान मंदिर भी है, जो धार्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों के लिए प्रसिद्ध है।

2. गिल्बर्ट ट्रेल

प्राकृतिक प्रेमियों और वॉकिंग के शौकीनों के लिए यह एक आदर्श जगह है। यह पगडंडी देवदार और ओक के पेड़ों के बीच से गुजरती है और यहां की शांति आत्मा को सुकून देती है।

3. क्राइस्ट चर्च

1853 में बना यह चर्च कसौली की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। इसकी गोथिक शैली की वास्तुकला और रंगीन कांच की खिड़कियाँ देखने लायक हैं।

4. सनसेट पॉइंट

शाम के समय यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक होता है। पहाड़ियों के बीच सूरज को डूबते हुए देखना एक अविस्मरणीय अनुभव है।

5. कसौली ब्रुअरी

यह एशिया की सबसे पुरानी डिस्टिलरी मानी जाती है, जो अब भी संचालित हो रही है। यह ब्रिटिश काल की विरासत को संजोए हुए है।

कसौली में करने योग्य गतिविधियाँ

- प्राकृतिक ट्रेल्स पर वॉकिंग और ट्रेकिंग
- स्थानीय बाजारों में शॉपिंग (हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, जैम आदि)
- फोटोग्राफी और बर्ड वॉचिंग
- चर्चों और औपनिवेशिक इमारतों की खोज
- शांत वातावरण में ध्यान और योग

यात्रा का सर्वोत्तम समय

मार्च से जूनः गर्मियों में ठंडक का आनंद लेने के लिए उपयुक्त।

सितंबर से नवंबरः साफ आसमान और हरियाली देखने के लिए।

दिसंबर से फरवरीः बर्फबारी का आनंद लेने वालों के लिए बेहतरीन समय।

कैसे पहुँचे कसौली?

हवाई मार्गः निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ (लगभग 60 किमी) है।

रेल मार्गः निकटतम रेलवे स्टेशन कालका (लगभग 25 किमी) है, जहाँ से टैक्सी या बस ली जा सकती है।

सड़क मार्गः चंडीगढ़, शिमला, दिल्ली से सीधी बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं।

कसौली एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहाँ प्रकृति की गोद में शांति, सौंदर्य और इतिहास का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो जीवन की दौड़-भाग से दूर कुछ पल सुकून और ताजगी के साथ बिताना चाहते हैं।

पैसे बचाने के चक्कर में घर पर ही बनाती हैं मेकअप प्रोडक्ट्स, इन गलतियों से स्किन को हो सकता है भारी नुकसान

होममेड मेकअप प्रोडक्ट्स बनाते समय प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। कई बार लोग बिना प्रिज़र्वेटिव के क्रीम, जेल या ग्लॉस बनाकर स्टोर कर लेते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में बदबू आने लगती है, फंगस भी हो सकता है।

अपनी स्किन की खूबसूरती को निखारने के लिए अक्सर हम सभी मेकअप प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मार्केट में मिलने वाले मेकअप प्रोडक्ट्स ना केवल महंगे होते हैं, बल्कि इनमें कई तरह के केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिससे स्किन पर नेगेटिव असर पड़ता है। ऐसे में घर पर ही मेकअप प्रोडक्ट्स बनाना अच्छा विचार होता है। इनमें ना केमिकल्स होते हैं और ना ही कोई प्रिज़रवेटिव, जिसकी वजह से आपकी स्किन भी सेफ रहती है।

घर पर मेकअप प्रोडक्ट्स बनाना यकीनन अच्छा आइडिया है, लेकिन इसे सही तरह से बनाना बेहद जरूरी है। अक्सर घर पर मेकअप प्रोडक्ट्स बनाते समय हम कुछ छोटी-छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे ना केवल मेकअप प्रोडक्ट खराब होता है, बल्कि स्किन पर रैशेज़, पिंपल्स या जलन भी हो सकती है। तो चलिए आज इस लेख में हम आपको घर पर ही मेकअप प्रोडक्ट्स बनाते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियों के बारे में बता रहे हैं, जिनसे आपको बचना चाहिए-

अपनी स्किन टाइप का ध्यान ना रखना

जब आप मेकअप प्रोडक्ट घर पर बना रही हैं तो आपको अपनी स्किन टाइप का खास ख्याल रखना चाहिए। अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे स्किन को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मसलन, अगर आपकी स्किन ड्राई है और ऑयली प्रोडक्ट्स स्किन पर लगाती हैं तो इससे चेहरे पर पिंपल, रूखापन या रैशेज हो सकते हैं। इसी तरह, नारियल तेल ड्राय स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन ऑयली स्किन पर लगाने से पोर्स बंद हो जाते हैं। इसलिए, सबसे पहले अपनी स्किन टाइप समझो, फिर उसी हिसाब से चीज़ें चुनो।

पैच टेस्ट ना करना

भले ही आप घर पर मेकअप प्रोडक्ट बना रही हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से सुरक्षित समझें। कई बार घर पर बने मेकअप प्रोडक्ट्स भी आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी नया होममेड मेकअप प्रोडक्ट सीधे चेहरे पर लगाने की गलती ना करें। इससे एलर्जी, जलन या रेडनेस हो सकती है या फिर स्किन छिल भी सकती है। बेहतर होगा कि आप किसी भी नए प्रोडक्ट को पहले बाजू के अंदर या कान के पीछे लगाकर 24 घंटे देखो। इसके बाद ही इसे इस्तेमाल करें।

प्रिज़र्वेटिव को स्किप करना

होममेड मेकअप प्रोडक्ट्स बनाते समय प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करना जरूरी होता है। कई बार लोग बिना प्रिज़र्वेटिव के क्रीम, जेल या ग्लॉस बनाकर स्टोर कर लेते हैं, जिससे कुछ ही दिनों में बदबू आने लगती है, फंगस भी हो सकता है। हालांकि, होममेड मेकअप प्रोडक्ट्स विटामिन ई ऑयल, रोज़मेरी एक्सट्रैक्ट या कोई नैचुरल प्रिज़र्वेटिव इस्तेमाल करो। इसे फ्रिज में रखो और छोटे बैच में बनाओ।

'आप' की झुग्गीवासियों के नाम पर बुलाई जनसभा पूरी तरह फलोप रही: 'वीरेन्द्र सचदेवा'

सुषमा रानी

नई दिल्ली 29 जून : दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की आम आदमी पार्टी की झुग्गीवासियों के नाम पर बुलाई जनसभा पूरी तरह फलोप रही और जब ₹आपऱ नेता बोले तो एक बार फिर उनका अराजक असंवैधानिक रूप देखने को मिला।

वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है की पूरा आम आदमी पार्टी नेतृत्व गत लगभग एक माह से भ्रम फैला रहा था पर दिल्ली के झुग्गी वासियों ने ₹आपऱ के इस झूठे अभियान को ना सिर्फ नाकार दिया बल्कि झुग्गीवासी ₹आपऱ नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं की दस साल की सरकार ने झुग्गी वासियों को बेहतर जीवन देने के लिए क्या किया ?

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा की लगभग 5 माह पूर्व चुनाव हारी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय आदि जब झुग्गी वालों के नाम पर एकत्र अपने कार्यकर्ताओं को प्रधान मंत्री आवास में घुसने के लिए भड़का रहे थे उस वक्त दिल्ली का आम झुग्गीवासी पूछ रहा था की केजरीवाल बतायें उन्होने दस साल में खुद के लिए शीशमहल बनाया पर गरीबों को नरेला बवाना में बने फ्लैट्स आवंटित क्यों नही किए ?

उन्होंने कहा की अरविंद केजरीवाल वो दोहरे चेहरे वाले नेता हैं जो आज गरीब झुग्गीवालों के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं पर कोविड़काल में इन्ही झुग्गीवासी गरीबों को संरक्षण देने की जगह गांव भगाया था।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा है की प्रधान मंत्री आवास पर हमले की घोषणा केजरीवाल एवं गोपाल राय के काले नक्सलवादी चेहरे को फिर सामने लाये हैं और वो समझ लें की उनके शब्दों के लिए सभ्य समाज में कोई जगह नही है।

उन्होंने कहा है की भाजपा सरकार नालों पर, रेल लाइनों के पास नारकीय जीवन जीने को मजबूर झुग्गीवालों को बेहतर जीवन देने को कटिबद्ध है। हमने जिस तरह कालका जी, जेलरवाला बाग, कलंदर कॉलोनी, कठपुतली कॉलोनी पुनः बसाया है उसी तरह आगे भी जहां झुग्गी वहां मकान अभियान को आगे बढ़ाकर झुग्गी वालों को नया जीवन देगी।

जेएनयू कुलपति ने प्रवेश परीक्षा की छात्रसंघ की मांग ठुकराई, कहा- डीन ने नहीं दी सहमति; सीयूईटी को बताया लोकतांत्रिक

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति ने छात्रसंघ की प्रवेश परीक्षा की मांग को खारिज कर दिया है क्योंकि डीन सहमत नहीं हैं और सीयूईटी को अधिक लोकतांत्रिक बताया है। सीयूईटी में आरक्षित श्रेणी के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। छात्रसंघ ने मांगों को पूरा न होने तक हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी है। उन्होंने पीएचडी प्रवेश के लिए जेएनयूईई को अनिवार्य करने की मांग की है।

नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुलपति ने छात्रसंघ (जेएनयूएसयू) की खुद की प्रवेश परीक्षा से प्रवेश देने की मांग ठुकरा दी है। उन्होंने कहा, सभी केंद्रों के डीन ने सहमति नहीं दी है। उन्होंने सीयूईटी को अधिक लोकतांत्रिक बताया है।

कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलिपुड़ी पंडित ने कहा, उन्होंने पूर्व में भी छात्रसंघ से मुलाकात की है और जेएनयू प्रवेश परीक्षा (जेएनयूईई) को लेकर सभी डीन और चेयरपर्सन्स के साथ व्यापक चर्चा की थी। मैंने एक साल पहले सभी डीन से कहा था कि वे लिखित में दें कि उनकी स्कूल या केंद्र जेएनयूईई आयोजित कराने की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन, किसी ने भी लिखित में सहमति नहीं दी। कई डीन ने नेट और सीयूईटी के पक्ष में राय दी।

सीयूईटी परीक्षा को अधिक लोकतांत्रिक माना गया

कुलपति ने कहा कि सीयूईटी परीक्षा को अधिक लोकतांत्रिक माना गया, क्योंकि इसकी पहुंच व्यापक है और इसमें आरक्षित श्रेणी के छात्रों का प्रदर्शन भी बेहतर रहा है। छात्र संघ को दिए जवाब में उन्होंने कहा, डीन आफ एडमिशन ने आपके साथ तथ्य, आंकड़े और डेटा साझा कर समझाया कि सीयूईट अधिक समान अवसर देने वाली परीक्षा है।

उन्होंने छात्रसंघ के एक सदस्य द्वारा अकेले मिलने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, "आप सभी छात्रों के लिए मिलकर लड़ते हैं, इसलिए जेएनयूएसयू की एकता बनाए रखना जरूरी है। अगर आप पूरी टीम के साथ आएंगे तो मैं आपसे फिर मिलूंगी।

कुलपति ने एक जुलाई को मिलने का समय दिया

कुलपति ने बताया कि छात्रावासों से जुड़ी अन्य समस्याओं के लिए डीओएस और उनकी टीम से संपर्क किया जा सकता है क्योंकि विश्वविद्यालय में निर्णय प्रक्रिया विकेंद्रीकृत है। आपके मुद्दों पर डीओएस और डीओए और मेरे स्तर पर पहले ही विस्तार से चर्चा हो चुकी है। यदि आप चाहें तो हम फिर से एक बैठक कर सकते हैं। कुलपति के कहने के बाद छात्रसंघ ने मिलने की मांग रखी है। चारों पदाधिकारियों को कुलपति ने एक जुलाई को मिलने का समय दिया है।

मांगें मानने तक हड़ताल रहेगी जारी

जेएनयूएसयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि मांगें मानने तक हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा, कई केंद्र व स्कूल के डीन ने जेएनयूईई के पक्ष में राय दी है। कुलपति से मिलकर हम इस पर चर्चा करेंगे। पीएचडी व अन्य प्रवेश के लिए जेएनयूईई को अनिवार्य किया जाए और वायवा व साक्षात्कार का वेटेज घटाकर 10-15 प्रतिशत किया जाए।

पीएचडी शोधार्थियों को दी गई छात्रावास खाली करने की नोटिस वापस ली जाए और शोध पूरा होने तक छात्रावास आवास सुनिश्चित किया जाए। छात्रों के खिलाफ चलाई जा रही मनमानी प्राक्टोरियल जांचों को रद किया जाए। मासिक कंटिंजेंसी ग्रांट (एमसीएम) को पांच हजार किया जाए और इसे 'तर्कसंगत' करने के लिए बनी समिति को खत्म किया जाए।

हर महीने की अंतिम रविवार को हमें यह अवसर मिलता है कि हम प्रधानमंत्री की बातों को सुन सके और उनसे प्रेरणा ले सके: बैजयंत जय पांडा

सुषमा रानी

नई दिल्ली, 29 जून : दिल्ली भाजपा द्वारा लगभग 6500 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे राष्ट्रीय और प्रदेश नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम को सुना।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मालवीय नगर विधानसभा में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक सतीश उपाध्याय के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना।

बैजयंत जय पांडा एवं वीरेन्द्र सचदेवा ने विधायक सतीश उपाध्याय द्वारा पूरे विधानसभा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 1.5 लाख पौधे लगाने के संकल्प की शुरुवात उनके कार्यालय के बाहर पेड़ लगा कर की। इस मौके पर भाजपा नेता राकेश सिन्हा और जिला अध्यक्ष रविन्द्र चौधरी भी उपस्थित थे।

कृष्णा नगर में केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिल्ली भाजपा के संगठन महामंत्री पवन राणा एवं विधायक डॉ अनिल गोयल सहित अन्य कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुना।

भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने आज चिराग दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम में सुना।

राष्ट्रीय संगठक वी. सतीश ने आज पटेल नगर में सतसंग सुनने आए भक्तों के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मन की बात सुना।

राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश ने जाटव शिवमंदिर कोटला रोड, दिल्ली गेट में ₹मन की बातऱ कार्यक्रम को भाजपा नेता अमित गुप्ता आदि के साथ सुना।

सांसद मनोज तिवारी ने आज बुराड़ी में जिला अध्यक्ष यू.के. चौधरी के साथ ₹मन की बातऱ कार्यक्रम को सुना और कहा कि कार्यक्रम में यमुना तट पर हुए योग का उल्लेख होना सिर्फ उत्तर पूर्वी लोकसभा ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली के लिए गर्व का विषय है।

दिल्ली भाजपा के महामंत्री और सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने विंडसर प्लेस पर और सांसद कमलजीत सहरावत ने मटियाला विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना।

मन की बात सुनने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए बैजयंत जय पांडा ने कहा कि हर महीने की अंतिम रविवार को हमें यह अवसर मिलता है कि हम प्रधानमंत्री की बातों को सुन सके, उनसे प्रेरणा ले सके और उनके बताए रास्तों पर चल सके। उन्होंने कहा कि भारत अब ट्रेकोमा मुक्त देश बन चुका है और साथ ही इसकी सफलता के लिए उन्होंने सभी हेल्थ वर्कर्स को बधाई दी।

पांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जो भी कार्य किए और जो भी योजनाएं चलाई वह देश और देशवासियों के हित में है। एक पेड़ मां के नाम अभियान भी देश और दिल्ली के लिए है। प्रदूषण से मुक्ती हो, इस संकल्प के साथ दिल्ली में भी भाजपा सरकार काम कर रही है और उसी कड़ी में आज पौधारोपण की शुरुआत भी मालवीय नगर विधानसभा में हो रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ₹मन की बातऱ कार्यक्रम एक सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा बल्कि अब तो यह जन जन का कार्यक्रम बन चुका है। लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विशेष संदेश और जानकारी के लिए इसे सुनना पसंद करते हैं क्योंकि भारत के किसी भी कोने में कुछ भी अलौकिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिघटनाएं होती है उसको अपने कार्यक्रम के माध्यम के साथ जन जन तक पहुँचाने का काम करते हैं।

सचदेवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यक्रम के माध्यम से कई नई जानकारी भी साझा करते हैं जैसे आज उन्होंने मेघालय का ईरी सिल्क के बारे में जिक्र किया जो वहाँ का धरोहर है।

इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में सरकार द्वारा इमरजेंसी लगाए जाने की भी जानकारी दी। ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था।इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।

राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 से नवाजे गए डॉ डीसी प्रजापति।

सुषमा रानी

डॉ डीसी प्रजापति को स्वास्थ्य क्षेत्र आज फेस ग्रुप द्वारा साहिबाबाद के होटल एलिगेंट में राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने पर प्रदान किया गया, ज्ञात रहे कि डॉ प्रजापति द्वारा 6000 से ज्यादा निःशुल्क चिकित्सा शिविर , नशा मुक्ति अभियान, यमुना सफाई अभियान, केंसर जागरूकता कार्यक्रम पिछले लगभग 2 दशक से चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष ही डॉ प्रजापति को वियतनाम का उच्चतम पुरस्कार इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड प्रदान किया गया था, पुरस्कार प्राप्त होने के बाद डॉ प्रजापति से जब पत्रकार ने पूछा कि इतने कम समय मे ये रिकार्ड कैसे सम्भव है, उन्होंने बताया कि देश के प्रति समर्पण होना चाहिए सब काम होता चला जाता है, और अब तो हमारे पास एबीसीए की सफल टीम है अब हम घर घर तक स्वास्थ्य लाभ पहुचायेंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग तकनीकी बनाम उन्नत अपडेट तेजी से परिष्कृत होते साइबर हमले व धोखाधड़ी

वैश्विक स्तरपर उन्नत व अपडेट होती साइबर ठगी-आरबीआई रिपोर्ट अनुसार भारत में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले घटे, परंतु रकम तीन गुना बढ़ी

पूरे विश्व के लिए साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम से लगातार बढ़नें वाली चुनौतीयों से निपटने तात्कालिक़ अपग्रेड की आवश्यकता बढ़ी-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ के आधुनिक प्रौद्योगिकी के बढ़ते क्रम में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो बैंक अकाउंट साइबर क्राइम से बहुत आगे बढ़कर अबव्हाट्सएप मेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित अनेकों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच गए है, तो इधर किसी लिंक पर क्लिक किया उधर आप साइबर क्राइम का शिकार हुए, जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है, जिसका संज्ञान लेकर अब यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी चौकन्ने हो गए हैं, थोड़ा सा भी डाउट हुआ या ब्रिच ऑफ़ टर्म एंड कंडीशन हुए, तो तुरंत वह मीडिया प्लेटफॉर्म लॉक कर दिया जाता है।अभी अनेकों लोगों के व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट लॉक कर दिए गए हैं जिस पर ब्रिच आफ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखकर आ रहे हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र इस आर्टिकल के माध्यम से पूरी दुनियाँ के मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उपयोगकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि अपने इंस्ट्रूमेंट क़ा आति सावधानी से उपयोग करें, जिसके बारे में नीचे पैराग्राफ में चर्चा की गई है।हमारा वहमीडिया प्लेटफॉर्म भी बंद कर दिया जा सकता है, जिसमें हमारे बहुमूल्य डाटा या ग्रुप होते हैं,नया नंबर लेकर के वह प्लैटफॉर्म तो चालू किया जा सकता है परंतु उसके सारे डेटा उड़ जाते हैं,, इसलिए हमें साइबर क्राइम वालों को कोई मौका नहीं देना है और बहुत ही सावधानी के साथ अपने इंस्ट्रूमेंट क़ा उपयोग करना है।चूँकि पूरे विश्व के लिए साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम क़ा लगातार बढ़नां एक चुनौती है तथा उससे निपटने तात्कालिक अपडेट की आवश्यकता बढ़ गई है, इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग तकनीकी बनाम उन्नत अपडेट तेजी से परिष्कृत होते साइबर क्राइम व धोखाधड़ी होने की संभावना है।

साथियों बात अगर हम वर्तमान समय में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ाने की करें तो, कई ऐसे मामले सामने आए हैं,जिसमें नकली पुलिस, सीबीआई ऑफिसर बनकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट किया गया और लाखों रुपये ठग लिए गए, इंटरनेट पर स्टोर जानकारी को एक्सेस करके ठग, लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। हालांकि,जिन लोगों के पास इंटरनेट नहीं है उनको भी ठग अपना शिकार बना ले रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिना इंटरनेट के उनके पास हमारी जानकारी कैसे है ?आज के दौर में अगर हम खुद को सुरक्षित नहीं रखते तो हम साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं,हम इससे बचने के लिए अगर ईमेल या किसी ऑनलाइन सर्विस का यूज कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसका पासवर्ड काफी मजबूत हो, गलती से भी अपने नाम, मोबाइल नम्बर या डेट ऑफ वर्थ को पासवर्ड न रखें, कोशिश करें कि हमेशाटू-फैक्टरऑथोटिकेशन का इस्तेमाल करें,अगर हमको कोई अनजान मेल या मैसेज आता है और उसमें कोई लिंक दिया गया है तो गलती से भी उसको खोलने की कोशिश न करें, अपने फोन को हमेशा अपडेट रखें,अगर कोई सिक्योरिटी फीचर अपडेट आता है तो उसको जरूर करें, इससे हमारा फोन सुरक्षित रहता है।अगर हम इंटरनेट यूज नहीं करते हैं तो भी ठग आराम से हमको शिकार बना सकते हैं,दरअसल, इसके लिए वे हमारे डेटा को दूसरी जगह से उठाते हैं, इसमें वे सोशल साइट्स, अस्पताल, दुकान या फिर सरकारी ऑफिस आदि जगहों से डेटा लीक करते हैं या फिर किसी तरह निकालते हैं, फिर इस डेटा का इस्तेमाल करके हमारे साथ ठगी के लिए करते हैं, कई लोगों का डेटा उनके किसी रिलेटिव के फोन से भी निकाल लिया जाता है। जो बेहद गंभीर बात है।

साथियों बात अगर हम आरबी आई की रिपोर्ट में वित्तवर्ष 2024-25 में धोखाधड़ी के मामले घटनें परंतु धोखाधड़ी की रकम तीन गुना बढ़ने की करें तो, धोखाधड़ी के अधिकांश मामले डिजिटल

भुगतान से जुड़े हैं आरबीआई की 2024-25 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार बैंकों से जुड़े धोखाधड़ी के कुल 23, 953 मामले सामने आए, जो 2023-24 की तुलना में 34 प्रतिशत कम रहे।किंतु2024-25 में 36,014 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई और यह रकम उससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 3 गुना अधिक रही।इसके दो मुख्य कारण रहे। पहला, उससे पिछले वित्त वर्ष में 18,674 करोड़ रुपये के 122 मामलों को धोखाधड़ी की श्रेणी से हटा दिया गया और दोबारा जांच के बाद इस वित्त वर्ष में फिर से उनकी शिकायत की गई। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के 27 मार्च, 2023 के फैसले का अनुपालन सुनिश्चित किया गया।रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में 1 लाख रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामले शामिल किए गए हैं। इसमें वे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें धोखाधड़ी कई साल पहले हुई थी मगर शिकायत इस साल दर्ज कराई गई थी। केंद्रीय बैंक के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वित्त वर्ष में धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा मामले निजी क्षेत्र के बैंकों ने आए। उन बैंकों में धोखाधड़ी के 14,233 मामले सामने आए हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र में कुल धोखाधड़ी के 59.4 प्रतिशत हैं।सरकारी बैंकों की तुलना में ये बहुत अधिक हैं। सरकारी बैंकों में धोखाधड़ी के केवल 6,935 मामले आए,जो कुल मामलों के 29 प्रतिशत ही रहे।किंतुसरकारी बैंकों में 25,667 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई, जो इस तरह के मामलों में शामिल रकम की कुल 71.3 प्रतिशत है। निजी क्षेत्र के बैंकों में कुल 10,088 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट में कहा, 'बैंक समूह के मुताबिक देखें तो पिछले 3 वर्षों में निजी क्षेत्र के बैंकों में सबसे अधिक धोखाधड़ी हुई मगर सबसे ज्यादा रकम की धोखाधड़ी सरकारी बैंकों में दिखी।रिजर्व बैंक के अनुसार संख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा धोखाधड़ी डिजिटल भुगतान (कार्ड/इंटरनेट) में हुई, जबकि रकम के हिसाब से ऋण श्रेणी में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी रही। कार्ड/इंटरनेट धोखाधड़ी के मामले निजी क्षेत्र के बैंकों में ज्यादा आए हैं, जबकि सरकारी बैंकों में कर्ज लेने में धोखाधड़ी ज्यादा की गई है।

साथियों बात अगर हमसीबीआई के अभियान ऑपरेशन चक्र-5 की करें तो,सीबीआई ने साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों से निपटने के लिए चल रहे प्रयासों के क्रम में, साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किए जा रहे खच्चर बैंक खातों के संबंध में पांच राज्यों में 42 स्थानों पर देशव्यापी तलाशी शुरू की है। खच्चर खाता वह बैंक खाता है जिसका उपयोग अवैध गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है।यह अभियान ऑपरेशन चक्र-5 के तहत पांच राज्यों – राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चलाया गया। जांच में पता चला है कि देश भर में विभिन्न बैंकों की सात सौ से अधिक शाखाओं ने लगभग साढे आठ लाख खच्चर खाते खोले हैं। एजेंसी ने बताया कि ये खाते या तो उचित केवाईसी मानदंडों या प्रारंभिक जोखिम मूल्यांकन के बिना खोले गए थे।तलाशी के दौरान,कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य, मोबाइल फोन, बैंक खाता खोलने के दस्तावेज, लेन-देन विवरण, केवाईसी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सीबीआई ने खच्चर बैंक खाते खोलने के संचालन और सुविधा में उनकी संलिप्तता के लिए नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरी कार्यवाही में बिचौलिए, एजेंट, खाताधारक और बैंककर्मी शामिल हैं।

साथियों बात अगर हम साइबर क्राइम को समझने की करें तो,साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर, नेटवर्क या डिजिटल उपकरणों के किसी अन्य सेट का उपयोग करके की जाने वाली असंख्य आपराधिक गतिविधियों का वर्णन करता है। साइबर अपराध को साइबर अपराधियों द्वारा की जानेवाली अवैध गतिविधियों की विशाल श्रृंखला के अंतर्गत माना जाता है।इनमें हैकिंग फ़िशिंग, पहचान की चोरी , रैनसमवेयर और मैलवेयर हमले, कई अन्य शामिल हैं। साइबर अपराध की पहुंच कोई भौतिक सीमा नहीं जानती। अपराधी, पीड़ित और तकनीकी अवसंरचना दुनिया भर में फैली हुई हैव्यक्तिगत और उद्यम स्तर पर सुरक्षा कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ, साइबर अपराध कई रूप लेता है और लगातार विकसित होता रहता है। बदले में, साइबर अपराधों की प्रभावी जांच, मुकदमा चलाने और उन्हें रोकने की क्षमता कई गतिशील चुनौतियों के साथ एक सतत लड़ाई है।साइबर अपराध व्यक्तियों, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा को नुकसान और रिकॉर्ड से समझौता हो सकता है। जैसे-जैसे तकनीक आगे बढ़ती है और अधिक से अधिक लोग मानक संचालन के लिए डिजिटल उपकरणों और नेटवर्क पर निर्भर होते हैं,साइबर अपराध का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिससे इससे बचाव के लिए कदम उठाना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।, वायरस के उदाहरणों में मेलिसा, आईलवयू और निमडा वायरस शामिल हैं - ये सभी फ़ाइलों को संक्रमित करने और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुँचाने के लिए तेज़ी से फैलते हैं। इसके अनेक उदाहरण यह भी है।डीडीओएस हमले, सॉफ्टवेयर चोरी फ़िशिंग घोटाले,चोरी की पहचान,ऑनलाइन उत्पीड़न साइबर आतंकवाद,,इंटरनेट या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए,ऑनलाइन विनाश के आम तौर पर बड़े कार्य, जैसे कि बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाना और भयावह खराबी पैदा करना, गोपनीय जानकारी चुराना, या राजनीतिक या सांस्कृतिक निहितार्थों के साथ प्रचार करना। साइबर आतंकवाद के मामले तेजी से परिष्कृत होते जा रहे हैं, जिससे साइबर सुरक्षा और संरक्षण पर अधिक मांग बढ़ रही है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग तकनीकी बनाम उन्नत अपडेट तेजी से परिष्कृत होते साइबर हमले व धोखाधड़ी, वैश्विक स्तरपर उन्नत व अपडेट होती साइबर ठगी- आरबीआई रिपोर्ट अनुसार भारत में बैंकों से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले घटे, परंतु रकम तीन गुना बढ़ी।पूरे विश्व के लिए साइबर अपराधों से जुड़ी कुल लागत और जोखिम से लगातार बढ़नें वाली चुनौतीयों से निपटने तात्काललिक़ अपग्रेड की आवश्यकता बढ़ी।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर हादसों पर लगेगी लगाम, एनएचएआई ने बनाया ये प्लान

गाजियाबाद में पुलिस और एनएचएआई अधिकारियों ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच नौ पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए बैठक की। दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने का लक्ष्य है। एबीईएस कॉलेज के पास निकास द्वार चौड़ा होगा डीएमई पर रेलिंग लगेगी। सर्विस रोड बनेगा डिवाइडर ऊंचे होंगे। यातायात बूथ बनेंगे और रम्बल स्ट्रिप लगाए जाएंगे।

गाजियाबाद। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे(डीएमई) और एनएच नौ पर 50 फीसदी हादसों को कम करने के लिए शनिवार को पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित अहम निर्णय लिए गए।

एनएच नौ पर एबीईएस कालेज के पास बने निकास और प्रवेश द्वार को चौड़ा किया जाएगा। वहीं डीएमई पर दोनों ओर यूपी गेट से डासना तक दोनों ओर रेलिंग लगाई जाएगी। जिससे पैदल चलने वाले लोग डीएमई को पार न कर सकें।

एडीसीपी यातायात सच्चिदानंद ने बताया कि हादसों को कम करने के लिए एनएचएआई के अधिकारियों के कार्ययोजना तैयार की गई है। निकास मार्गों पर रिफ्लेक्टिव साइनेज बोर्ड लगवाए जाएंगे। स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड का निर्माण कराया जाएगा।

बुलंदशहर रोड को एनएच नौ से के पास से चौड़ा कराया जाएगा। यहां से डिवाइडर को ऊंचा कराया जाएगा। जिससे लोग डिवाइडर को न कूद सकें। आइएमएस कॉलेज के पास यातायात निरीक्षक के लिए कार्यालय का निर्माण कराया जाएगा।

पुलिसकर्मियों के लिए बनेंगे ट्रैफिक बूथ

दिल्ली-सहारनपुर हाइवे पुस्ता उतार के पास लोनी साइड के दो पिलरों के बीच यातायात निरीक्षक के छह कार्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन और रिकवरी वाहनों का संचालन होगा। अंडरपास के निकट कुछ लोग विपरीत दिशा में चलने के आदी हो गए हैं।

दिल्ली-सहारनपुर हाइवे पुस्ता उतार के पास लोनी साइड के दो पिलरों के बीच यातायात निरीक्षक के छह कार्यालयों का निर्माण कराया जाएगा। एम्बुलेंस, पेट्रोलिंग वाहन और रिकवरी वाहनों का संचालन होगा। अंडरपास के निकट कुछ लोग विपरीत दिशा में चलने के आदी हो गए हैं।

विपरीत दिशा में चलने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई के लिए एएनपीआर कैमरे लगाए जाएंगे। एनएच नौ और डीएम पर प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। पुलिसकर्मियों के लिए 20 यातायात बूथ का निर्माण होगा। डीएमई और एनएच नौ पर रम्बल स्ट्रिप बनाए जाएंगे। यदि चालक को नींद आती है और वह दूसरी लेन में जाता है तो उसे पता चल जाएगा।

जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान कानपुर में फिर बवाल, बोतल , मजीरा और झुनझुना मारे : 10 घायल

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां रथ यात्रा निकालने के दौरान यहां फिर बवाल हो गया । इस दौरान लोगों ने रथयात्रा में निकलती हुई झांकियां और नृत्य कर रहे लोगों पर पानी की बोतल, मंजीरा, झुनझुना चला कर मारे। जिसमें 10 लोग घायल हो गए।

इस घटना के दौरान पुलिस और विधायक अमिताभ बाजपेई ने लोगों को समझा कर अलग कराया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। कुछ ही देर में फिर से रथ यात्रा निकालना शुरू हो गई। मारपीट में 10 लोग घायल हुए हैं।

घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक उस समय जनरलगंज इलाके से रथ यात्रा में झांकियां निकल रही थीं। इस दौरान श्री दोसर वैश्य नवयुवक मंडल के युवक वहां पहुंचे। तभी अचानक कुछ लोग मारपीट करने लगे। इसी दौरान कुछ लोग पानी की बोतल, कोलड्रिंक की बोतल, बर्फ उन पर फेंककर मारने लगे। मौके पर लोगों में अफरा-तफरी मच गई। उस वक्त यात्रा में छोटे बच्चे और महिलाएं भी काफी संख्या में शामिल थीं ।

घटना की जानकारी देते हुए श्री दोसर वैश्य नवयुवक मंडल के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि रथ यात्रा निकल रही थी। तभी कुछ लोगों ने अचानक कोल्डड्रिंक की बोतल फेंककर मारने लगे। इसके बाद मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि बीते शुक्रवार को भी झगड़ा करने की कोशिश की गई थी। शनिवार रात को कुछ लोगों ने प्रयास किया कि यात्रा उनके चौराहे से ना निकल सके। इसलिए ऐसा किया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि तहरीर मिलाने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

खोड़ा में पानी की किल्लत से लोग परेशान, नोएडा अथॉरिटी से अभी तक नहीं मिली अनुमति; अधर में लटकी गंगाजल योजना

खोड़ा में गंगाजल आपूर्ति योजना नोएडा प्राधिकरण से अनुमति न मिलने के कारण अटकी हुई है। जल निगम बीते डेढ़ साल से अनुमति मांग रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं मिला है। 183 करोड़ की अमृत योजना के तहत 164 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जानी है जिससे इलाके में पानी की समस्या दूर हो सके। अनुमति न मिलने से निवासियों को पानी खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

साहिबाबाद। खोड़ा में गंगाजल आपूर्ति की योजना कागजों से आगे नहीं बढ़ पा रही है। नोएडा प्राधिकरण ने अभी तक खोड़ा को गंगाजल देने की अनुमति नहीं दी है। जबकि जल निगम के उच्चाधिकारी बीते डेढ़ वर्ष से लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन अभी तक न तो अनुमति मिली है और न ही कोई जवाब मिला है।

अधिकारियों का कहना है कि जब तक अनुमति नहीं मिल जाएगी योजना आगे नहीं बढ़ पाएगी। इससे 183 करोड़ की अमृत योजना अटक गई है। खोड़ा को नोएडा से 50 एमएलडी गंगाजल की आपूर्ति होनी है।

गंगाजल की आपूर्ति के लिए नवंबर 2023 में बनी थी योजना

यह गंगाजल जल निगम नोएडा अथॉरिटी लिया जाना है। इसके बीते करीब डेढ़ वर्ष से जल निगम के महाप्रबंधक चार बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक भी अनुमति नहीं मिली है। जबकि 16 जनवरी को टेंडर खोल दिया गया था। इसके बाद तकनीकी टेंडर भी खोल दिया गया, लेकिन अनुमति नहीं मिलने से यह योजना अटक गई है।

जल निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक नोएडा अथॉरिटी गंगाजल देने की अनुमति नहीं देगी तब तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब फिर से पत्र लिखने की तैयारी कर रहे हैं।

अमृत योजना के तहत 164 किलोमीटर डलनी है लाइन

खोड़ा को गंगाजल देने के लिए अमृत योजना के तहत नवंबर 2023 योजना बनाई गई थी। इस पर करीब 183 करोड़ का बजट खर्च होना है। योजना के तरह पूरी खोड़ा कालोनी की गलियों में 164 किलोमीटर लंबी लाइन डाली जानी है। लेकिन योजना कागजों से आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है।

कमाई का बड़ा हिस्सा पानी खरीदने पर हो रहा खर्च

खोड़ा कालोनी में पानी की समस्या चरम पर है। यहां के लोग पीने से लेकर नहाने तक के लिए पानी खरीदते हैं। इससे कमाई का बड़ा हिस्सा पानी पर ही खर्च हो जाता है। कुछ लोगों ने सबमर्सिबल लगा रखे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका जितने पानी की टैंकर से आपूर्ति करता है वह सभी को नहीं मिल पाता है। इससे ज्यादातर लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। यहां बड़ी संख्या में पानी माफिया सक्रिय हैं।

डॉ. अरुणवीर सिंह का कार्यकाल 30 जून को हो जाएगा खत्म, राकेश सिंह संभालेंगे YEIDA के सीईओ का कार्यभार

ग्रेटर नोएडा। लंबे वक्त से यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे डॉ. अरुणवीर सिंह का कार्यकाल 30 जून को समाप्त हो जाएगा। सचिव मुख्यमंत्री आरके सिंह नए सीईओ का कार्यभार संभालेंगे। वह पहले भी यमुना प्राधिकरण में एसीईओ रह चुके हैं। सेवानिवृति के बाद शासन ने सात बार उनकी यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर पुनर्नियुक्ति की।

लगभग दस साल तक पद पर रहते हुए डॉ. अरुणवीर सिंह ने यमुना प्राधिकरण को कर्ज से उबार कर मुनाफे की संस्था बनाने के अलावा औद्योगिक पार्कों की परिकल्पना को साकार किया। गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर से आगे जाकर यमुना प्राधिकरण के फेज दो में शामिल राया व टप्पल अर्बन सेंटर का मास्टर प्लान तैयार कराया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर हेरिटेज सिटी, फिल्म सिटी, सेमी कंडक्टर पार्क की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है।

2015 में सीईओ का पद पर नियुक्त हुए थे डॉ. अरुणवीर सिंह

डॉ. अरुणवीर सिंह की यीडा में तैनाती अपर मुख्य कार्यपालक के पद पर हुई थी। बाद में उन्हें पदोन्नति देते हुए 2015 में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पद सौंपा। सपा सरकार में सीईओ पद संभालने के बाद प्रदेश में भाजपा सरकार के दौरान भी उन्हें पद पर बनाए रखा गया। उन्होंने साढ़े सात हजार रुपये के कर्ज में डूबे यीडा को उबार कर पांच हजार करोड़ रुपये की लाभांश देने वाली संस्था के रूप में बदल दिया।

कर्ज के कारण एक समय यमुना प्राधिकरण को नोएडा, ग्रेटर नोएडा में समायोजित करने की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी, सीईओ ने किसानों से साथ जमीनी विवाद को निपटाया, हाई कोर्ट में लंबित जमीनी प्रकरणों को हल कराया। 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी। प्रदेश का सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण, विकासकर्ता कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी के चयन में अहम भूमिका निभाई।

कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की सफलता के साक्षी रहे अरुणवीर सिंह

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही महत्वाकांक्षी परियोजना फिल्म सिटी, मथुरा में हेरिटेज सिटी, टप्पल में मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क, प्रदेश की पहली सेमी कंडक्टर इकाई और मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, टाय पार्क के विकास का रास्ता साफ किया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही महत्वाकांक्षी परियोजना फिल्म सिटी, मथुरा में हेरिटेज सिटी, टप्पल में मल्टी माडल लाजिस्टिक पार्क, प्रदेश की पहली सेमी कंडक्टर इकाई और मेडिकल डिवाइस पार्क, अपैरल पार्क, टाय पार्क के विकास का रास्ता साफ किया।

2009 में आई पहली आवासीय भूखंड योजना के आवंटियों को कब्जा दिलाने के साथ नामचीन कंपनियों को यीडा क्षेत्र में जमीन आवंटन किया। इससे निवेश का माहौल बेहतर होने से यीडा को आर्थिक मजबूती मिली। जेवर प्रदेश का पहला सबसे तेजी से विकसित क्षेत्र बन गया है। शिफ्टिंग पालिसी, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लीजबैक प्रकरणों की जांच उनके नेतृत्व में एसआइटी गठित को सौंपी गई।

गाजियाबाद में जमकर गरजा बुलडोजर , जीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मोरटी गांव में एक बड़ी ध्वस्तीकरण कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रवर्तन टीम ने करीब सात हजार वर्ग गज में बन रही एक अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। कॉलोनाइजर ने विरोध किया लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया।

गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की प्रवर्तन टीम ने जोन-एक के गांव मोरटी में करीब सात हजार वर्ग गज में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया। इस दौरान कॉलोनाइजर ने प्रवर्तन टीम का विरोध किया, लेकिन पुलिसबल ने उन्हें मौके से हटाते हुए मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी।

मोरटी के खसरा नंबर 352 में करीब एक हजार वर्ग मीटर, खसरा संख्या 175 व 176 में छह हजार वर्ग मीटर जमीन पर कॉलोनाइजर अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में निर्माण को ध्वस्त किया।

इस दौरान बुलडोजर से अवैध कॉलोनी की सड़क, प्लॉटिंग और चारदीवारी को तोड़ा गया। प्राधिकरण की ओर से लोगों को सलाह दी गई कि अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में भूखंड व भवनों का क्रय-विक्रय न करें।

इंदिरापुरम विस्तार योजना में ड्रेनेज, सीवरेज और सड़क निर्माण में तेजी

इंदिरापुरम विस्तार योजना में ऐसे आवंटियों को जल्द कब्जा मिलेगा, जिन्होंने हाल में जीडीए की नीलामी प्रक्रिया के दौरान भूखंड खरीदे हैं। प्राधिकरण के अभियंत्रण अनुभाग द्वारा भूमिगत पानी की लाइन, सीवर और ड्रेनेज कार्य अंतिम चरण में है।

उक्त जानकारी देते हुए जीडीए वीसी अतुल वत्स ने बताया कि योजना के तहत यहां बडे हिस्से में सडक का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इंदिरापुरम विस्तार में विकास कार्य तेजी के साथ पूरा करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई थी। करीब तीन करोड की लागत से विकास कार्य कराये जा रहे हैं। श्मशान घाट के आसपास की दीवार के निर्माण का कार्य जारी है।

उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा जल्द रिक्त भूखंडों की भी नीलामी प्रक्रिया भी आरंभ होगी। इंदिरापुरम विस्तार में जिस जमीन पर यह योजना निकाली गई है उस समय 34,544 वर्ग मीटर का भूखंड ग्रुप हाउसिंग के लिए प्रस्तावित था। ग्रुप हाउसिंग के लिए प्रस्तावित भूखंड को नीलाम नहीं किया जा सका था।

कमेटी गठित कर प्रस्तावित भूखंड को छोटे भूखंडों में तब्दील करने का प्रस्ताव बोर्ड में रखा गया। बोर्ड की स्वीकृति के बाद 300 से 578 वर्ग मीटर साइज के भूखंडों में इसे विभाजित किए गए। उन्होंने बताया कि योजना में व्यवसायिक गतिविधि के लिए भी भूखंड प्रस्तावित किए गए। ताकि, आवंटी यहां अपना आशियाना बनाए तो पास में ही उन्हें जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध हो सकें।

सुपरटेक केपटाउन पर नोएडा अथॉरिटी ने लगाया 35.80 लाख का जुर्माना, एनजीटी के नियमों का हो रहा था उल्लंघन

नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक केपटाउन सोसायटी पर एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर 35 .80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सोसायटी बिना शोधित किए सीवर का जल नाले में बहा रही थी। प्राधिकरण ने पर्यावरणीय कानूनों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई की है। सोसायटी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई है।

नोएडा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के नियमों का उल्लंघन कर बिना शोधित किए सीवर का जल नाले में बहाया जा रहा था, जिस पर नोएडा प्राधिकरण ने शुक्रवार को सेक्टर-74 स्थित सुपरटेक केपटाउन सोसायटी में सीवर कनेक्शन काट दिया गया था।

उसके बाद सोसायटी पर प्राधिकरण के जल खंड प्रथम की ओर से 35 लाख 80 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया है। बताया जाता है कि यह कार्रवाई प्राधिकरण ने पर्यावरणीय कानून जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, ठोस अपशिस्ट 2000 एवं 2016 के उल्लंघन पर की है।

इस लापरवाही को लेकर समय-समय पर सोसायटी को अवगत भी कराया गया लेकिन न तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) को क्रियाशील किया गया, न ही सीवरेज जल को शोधित किया गया। सोसायटी एओए के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने के लिए कोतवाली 113 में जल खंड प्रथम प्रबंधक पवन वर्णवाल की ओर से शिकायत दी है।

बता दें कि 27 जून को प्राधिकरण सीईओ डॉ. लोकेश एम शहर का औचक निरीक्षण करने निकले थे। निरीक्षण के दौरान सोसायटी से निकलने वाले सीवरेज जल को तीन स्थानों पर देखा कि वह मुख्य ड्रेन में बिना शोधित किए ही बहाया जा रहा था। जांच करने पर सामने आया कि यह पूरी तरह से अनशोधित जल है। जिसके बाद प्राधिकरण की जल खंड की टीम सक्रिय किया।

तीन स्थानों पर सीवरेज फ्लो के कनेक्शन को काटा गया। साथ ही नोटिस जारी करते हुए 35 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। संबंधित थाने में एफआइआर भी कराई जा रही है। बता दे अब आठ सोसायटी पर जुर्माना और एफआइआर दर्ज कराई जा चुकी है।

रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं लगाने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

जिलाधिकारी ने भूगर्भ जल विभाग के अधिकारियों से कहा कि बारिश के दौरान आवासीय सोसायटी, अपार्टमेंट सरकारी भवनों, कार्यालय आदि में भी भूगर्भ जल रिचार्ज स्ट्रक्चर सिस्टम की स्थिति की गहन समीक्षा की जाए एवं सभी से रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय होने की रिपोर्ट प्राप्त की जाए।

जिनके द्वारा रिपोर्ट नहीं दी जा रही उनके खिलाफ पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए। साथ ही निर्देश दिए कि सभी सरकारी कार्यालयों, भवनों व हाइराइज सोसायटियों में लगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सक्रिय रहने चाहिए।

हुंडई वेन्यू फेसलिफ्टकी टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी झलक, जानें क्या मिली जानकारी, कब तक हो सकती है लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

देश में सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इस सेगमेंट में हुंडई की ओर से जल्द ही Hyundai Venue Facelift को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इसके फेसलिफ्ट वर्जन में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। इसे कब तक लॉन्च किया जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में सब फोर मीटर एसयूवी की सबसे ज्यादा मांग होती है। इस सेगमेंट में सभी निर्माताओं की ओर से कई बेहतरीन उत्पादों को ऑफर किया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक Hyundai Venue Facelift को भी जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इस एसयूवी को एक बार फिर से टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। फेसलिफ्ट वर्जन की क्या जानकारी सामने आई है। कब तक इसे लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी Hyundai Venue Facelift

हुंडई की ओर से भारतीय बाजार में जल्द ही वेन्यू फेसलिफ्ट को लाने की तैयारी की जा रही है। हाल में ही इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देखी गई एसयूवी में कई बदलाव किए जा सकते हैं।

क्या होंगे बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के फ्रंट से लेकर रियर तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसमें नया बंपर, एलईडी लाइट्स कनेक्टिड डीआरएल, नई ग्रिल के साथ ही रियर में भी इसी तरह के बदलाव किए जा सकते हैं। वहीं इंटीरियर में भी कई बदलावों को किया जा सकता है।

इंजन में नहीं होगा बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक एसयूवी के इंजन में किसी भी तरह के बदलाव को नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा इंजन के विकल्प ही दिए जाएंगे। जिसके साथ मैनुअल, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन भी ऑफर किए जाएंगे।

कीमत में होगी मामूली बढ़ोतरी

मौजूदा वेन्यू को बाजार में 7.94 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है। लेकिन फेसलिफ्ट वर्जन की कीमत में 10 से 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की जा सकती है।

कब तक होगी लॉन्च

निर्माता की ओर से इस एसयूवी के फेसलिफ्ट को अक्टूबर 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी लॉन्च को लेकर निर्माता ने औपचारिक जानकारी नहीं दी है।

किनसे है मुकाबला

हुंडई की ओर से वेन्यू को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला Maruti Suzuki Brezza, Kia Sonet, Kia Syros, Mahindra XUV 3XO, Tata Nexon, Skoda Kylaq जैसी एसयूवी के साथ होता है।

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या है और क्यों जरूरी है? जानिए कैसे काम करता है ये सिस्टम

परिवहन विशेष न्यूज

1 अप्रैल 2026 से सभी दोपहिया वाहनों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) अनिवार्य होगा चाहे इंजन क्षमता कुछ भी हो। ABS तेज ब्रेक लगाने पर गाड़ी को फिसलने से बचाता है। यह सिस्टम व्हील्स की स्पीड को मॉनिटर करता है और जरूरत पड़ने पर ब्रेक प्रेशर को कम-ज्यादा करता है जिससे गाड़ी कंट्रोल में रहती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। भारत में सड़क हादसों की संख्या कम करने और राइडर्स की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ऐलान किया है कि 1 अप्रैल 2026 से सभी नई दोपहिया गाड़ियों में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) लगाना अनिवार्य होगा, चाहे उनकी इंजन कैपेसिटी कुछ भी हो। आइए विस्तार में जानत हैं कि ABS क्या होता है, कैसे काम करता है और यह दोपहिया वाहनों में क्यों जरूरी है?

अब क्यों जरूरी हो गया ABS?

भारत में होने वाले सड़क हादसों का करीब 44% हिस्सा टू-व्हीलर्स से जुड़ा होता है। बाजार में बिकने वाले करीब 45% टू-व्हीलर्स 125cc से कम इंजन क्षमता के होते हैं। अब तक इन छोटे इंजन वाली बाइक्स और स्कूटर्स में सिर्फ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम (CBS) दिया जाता था। CBS आगे और पीछे के ब्रेक को एकसाथ एक्टिव करता है, जिससे ब्रेकिंग थोड़ी बेहतर होती है, लेकिन ABS की तुलना में CBS कम प्रभावी साबित होता है।

ABS क्या होता है और कैसे करता है काम?

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) एक सुरक्षा फीचर है, जो बाइक को तेज ब्रेक लगाने पर स्लिप या स्किड होने से बचाता है। जब आप अचानक जोर से ब्रेक लगाते हैं, तो व्हील्स लॉक हो सकते हैं और गाड़ी फिसल सकती है। ABS व्हील्स की स्पीड को लगातार सेंसर के जरिए मॉनिटर करता है। जैसे ही कोई व्हील लॉक होने लगे, सिस्टम तुरंत ब्रेक प्रेशर को कम करता है और फिर बढ़ाता है। इसे पल्सिंग एक्शन कहा जाता है। इस प्रक्रिया के चलते व्हील्स लॉक नहीं होते और गाड़ी कंट्रोल में रहती है। इसका फायदा ये होता है कि फिसलन भरी या गीली सड़कों पर बाइक जल्दी और सुरक्षित रुकती है।

किन गाड़ियों पर होगा लागू?

नए नियम के तहत 1 अप्रैल 2026 के बाद बिकने वाली हर नई बाइक और स्कूटर में ABS जरूरी होगा। कुछ कंपनियां पहले ही अपनी 125cc बाइक्स में ABS देना शुरू कर चुकी हैं। उदाहरण के तौर पर, Hero Xtreme 125R इस समय भारत की सबसे सस्ती 125cc ABS बाइक है।

कीमत पर क्या असर पड़ेगा?

इस नियम से गाड़ियों की कीमत पर असर पड़ेगा। उम्मीद है कि एंट्री-लेवल बाइक्स और स्कूटर्स की कीमतों में 5,000 रुपये से 7,000 रुपये तक का इजाफा हो सकता है। हालांकि, ये एक जरूरी खर्च है क्योंकि आपकी सुरक्षा किसी भी कीमत से ज्यादा कीमती है।

रेनॉल्ट ट्राइबर फेसलिफ्ट टेस्टिंग के दौरान फिर दिखाई दी, जल्द हो सकती है भारत में लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

रेनो भारतीय बाजार में जल्द ही Renault Triber Facelift लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। टेस्टिंग के दौरान हाल ही में इसे फिर देखा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके फेसलिफ्ट वर्जन में कई बदलाव किए जा सकते हैं। हाल में देखी गई यूनिट से क्या जानकारी सामने आई है। इसे कब तक भारतीय बाजार में औपचारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में रेनो की ओर से कई सेगमेंट में वाहनों की बिक्री की जाती है। निर्माता की ओर से जल्द ही बजट एमपीवी Renault Triber Facelift को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे हाल में ही टेस्टिंग के दौरान फिर देखा गया है। अब इस एमपीवी की क्या जानकारी सामने आई है। इसे कब तक भारत में लॉन्च किया जा सकता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

हो रही Renault Triber Facelift की तैयारी

रेनो की ओर से ट्राइबर के फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बजट एमपीवी को लॉन्च करने से पहले इसकी टेस्टिंग (Renault Triber facelift testing) की जा रही है। टेस्टिंग के दौरान इस गाड़ी को हाल में फिर से देखा गया है।

क्या मिली जानकारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल में एमपीवी के फेसलिफ्ट को सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है। हालांकि इस यूनिट को भी पूरी तरह से ढंका गया था, लेकिन फिर भी इसके फ्रंट की कुछ जानकारी सामने आई है। इसमें नया बंपर, हेडलाइट और ग्रिल को दिया जाएगा। जिससे यह मौजूदा वर्जन के मुकाबले अलग नजर आएगी।

पहले क्या मिली थी जानकारी

इसके पहले भी इस एमपीवी को टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। तब भी इसे अच्छी तरह से कवर किया गया था। लेकिन इसके डिजाइन की ही कुछ जानकारी सामने आ पाई थी। एमपीवी के रियर में भी बंपर और टेल लाइट्स में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा इसके इंटीरियर में भी बदलाव किए जा सकते हैं।

इंजन में नहीं होगा बदलाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो की ओर से ट्राइबर एमपीवी के इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा इंजन को ही ऑफर किया जाएगा। फिलहाल इस एमपीवी में एक लीटर की क्षमता का इंजन दिया जाता है जिसके साथ मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन को दिया जाता है। इस एमपीवी को पेट्रोल के साथ ही सीएनजी में भी ऑफर किया जाएगा।

कब होगी लॉन्च

रिपोर्ट्स के मुताबिक रेनो की ओर से ट्राइबर एमपीवी के इंजन में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें मौजूदा इंजन को ही ऑफर किया जाएगा। फिलहाल इस एमपीवी में एक लीटर की क्षमता का इंजन दिया जाता है जिसके साथ मैनुअल और एएमटी ट्रांसमिशन को दिया जाता है। इस एमपीवी को पेट्रोल के साथ ही सीएनजी में भी ऑफर किया जाएगा।

कब होगी लॉन्च

निर्माता की ओर से अभी इस बारे में औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे साल के आखिर या अगले साल के शुरू तक भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है।

किआ सोनेट के बेस वेरिएंट को है घर लाना, एक लाख रुपये की अग्रिम भुगतान के बाद देनी होगी कितनी ईएमआई

कार फाइनेंस योजना किआ की ओर से देश में कई सेगमेंट के वाहनों को ऑफर किया जाता है। निर्माता की ओर से कॉम्पैक्ट SUV के तौर पर ऑफर की जाने वाली Sonet के बेस वेरिएंट को अगर आप भी खरीदने का मन बना रहे हैं तो एक लाख रुपये देने के बाद कितने रुपये (Kia Sonet EMI) हर महीने देकर इसे खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं।

नई दिल्ली। साउथ कोरियाई वाहन निर्माता Kia की ओर से भारतीय बाजार में सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में Sonet को बिक्री के लिए उपलब्ध करवाया जाता है। अगर आप भी कंपनी की Sonet के बेस वेरिएंट HTE को खरीदने का मन बना रहे हैं और एक लाख रुपये की डाउनपेमेंट करने के बाद गाड़ी को घर लाना चाहते हैं, तो हर महीने कितने रुपये की EMI देनी होगी। हम इसकी जानकारी आपको इस खबर में दे रहे हैं।

Kia Sonet Price

वाहन निर्माता Kia की ओर से Sonet को सब फोर मीटर एसयूवी सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। कंपनी की इस एसयूवी की एक्स शोरूम (Kia Sonet HTE Price) कीमत आठ लाख रुपये है। इस गाड़ी को अगर दिल्ली में खरीदा जाता है तो करीब 56 हजार रुपये आरटीओ और करीब 37 हजार रुपये इंश्योरेंस के देने होंगे। इसके साथ ही एसयूवी के लिए करीब सात हजार रुपये फास्टैग और अन्य चार्ज के भी देने होंगे। जिसके बाद Kia Sonet HTE on road price करीब 9.04 लाख रुपये के आस-पास हो जाती है।

एक लाख Down Payment के बाद कितनी EMI

अगर आप इस गाड़ी के बेस वेरिएंट HTE को खरीदते हैं, तो बैंक की ओर से एक्स शोरूम कीमत पर ही फाइनेंस किया जाएगा। ऐसे में एक लाख रुपये की डाउन पमेंट करने के बाद आपको करीब 8.04 लाख रुपये को बैंक से फाइनेंस करवाना होगा। बैंक की ओर से अगर आपको 9 फीसदी ब्याज के साथ सात साल के लिए 8.04 लाख रुपये दिए जाते हैं, तो हर महीने 12940 रुपये हर महीने की EMI आपको अगले सात साल के लिए देनी होगी।

कितनी महंगी पड़ेगी कार

अगर आप 9 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 8.04 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 12940 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Sonet के बेस वेरिएंट HTE के लिए करीब 2.82 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 11.86 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे होता है मुकाबला

Kia की ओर से Sonet को कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Breeza, Tata Nexon, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Renault Kiger, Kia Syros, Skoda Kylaq, Mahindra XUV 3XO जैसी Sub Four Meter SUVs के साथ होता है।

अगर आप 9 फीसदी की ब्याज दर के साथ सात साल के लिए 8.04 लाख रुपये का बैंक से Car Loan लेते हैं, तो आपको सात साल तक 12940 रुपये की EMI हर महीने देनी होगी। ऐसे में सात साल में आप Kia Sonet के बेस वेरिएंट HTE के लिए करीब 2.82 लाख रुपये बतौर ब्याज देंगे। जिसके बाद आपकी कार की कुल कीमत एक्स शोरूम, ऑन रोड और ब्याज मिलाकर करीब 11.86 लाख रुपये हो जाएगी।

किनसे होता है मुकाबला

Kia की ओर से Sonet को कॉम्पैक्ट साइज एसयूवी के तौर पर ऑफर किया जाता है। कंपनी की ओर से इस गाड़ी का बाजार में सीधा मुकाबला Maruti Breeza, Tata Nexon, Hyundai Venue, Nissan Magnite, Renault Kiger, Kia Syros, Skoda Kylaq, Mahindra XUV 3XO जैसी Sub Four Meter SUVs के साथ होता है।

2029 तक होंडा भारत में लॉन्च करेगी 5 नई कारें, नई 6th-जेन सिटी समेत हाइब्रिड और ईवी कारें शामिल

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय बाजार में हाइब्रिड कारों की बढ़ती मांग को देखते हुए Honda नए PF2 प्लेटफॉर्म पर आधारित तीन हाइब्रिड कारें लाने की तैयारी में है। कंपनी 2027 में 7-सीटर SUV 2028 में Honda City का छठा जेनरेशन मॉडल और एक Sub-4 मीटर SUV लॉन्च करेगी। Honda हाइब्रिड कारों के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है जिसकी शुरुआत 2026 में EV Elevate से होगी।

नई दिल्ली। पिछले कुछ वर्षों से भारतीय बाजार में हाइब्रिड कारों की मांग बढ़ी है। कार निर्माता कंपनियां पेट्रोल-डीजल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बीच की खाई को भरने के लिए तेजी से हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। इस रेस में अब Honda भी शामिल हो चुकी है। हाल के समय में होंडा के पास भारत में सिर्फ एक हाइब्रिड कार City e:HEV है, लेकिन कंपनी अब ज्यादा अफोर्डेबल हाइब्रिड मॉडल लाने की तैयारी कर रही है, जिनकी शुरुआती कीमत करीब 15 लाख रुपये हो सकती है।

नई होंडा हाइब्रिड कारें

कंपनी ने भारत में नए PF2 मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होंगी। इस प्लेटफॉर्म की खासियत है कि इसे मल्टी-एनर्जी यानी पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तीनों तरह के पावरट्रेन को सपोर्ट करने के लिए तैयार किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर बनी गाड़ियां सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी एक्सपोर्ट किया जाएगा।

आने वाली Honda हाइब्रिड कारें

होंडा भारतीय बाजार में तीन हाइब्रिड कारें लेकर आने वाली है। इन तीनों को ही PF2 प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। 2027 में कंपनी नई 7-सीटर SUV लेकर आएगी, जिसे Honda Elevate से ऊपर रखा जाएगा। इसमें Honda Elevate वाला 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और मजबूत हाइब्रिड दिया जा सकता है।

इसके बाद साल 2028 में कंपनी Honda City का छठा जेनरेशन मॉडल लेकर आएगी। इसमें नॉर्मल पेट्रोल और मजबूत हाइब्रिड दोनों ऑप्शन मिलेंगे। प्रोडक्शन मई 2028 से शुरू होने की संभावना है।

होंडी की तीसरी कार नई Sub-4 मीटर SUV होने वाली है। इसमें भी 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन हो सकता है। इसे भी बाकी दोनों की तरह ही PF2 प्लेटफॉर्म पर ही तैयार किया जाएगा।

Honda के EV प्लान्स

होंडा हाइब्रिड कार के साथ ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर भी फोकस कर रही है। इसकी पहली इलेक्ट्रिक कार EV Elevate पर बेस्ड हो सकती है, जिसे साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार 2029 तक PF2 प्लेटफॉर्म पर आधारित लॉन्च किया जाएगा, और इसे Elevate से नीचे पोजिशन किया जाएगा।

होंडा हाइब्रिड कार के साथ ही इलेक्ट्रिक सेगमेंट पर भी फोकस कर रही है। इसकी पहली इलेक्ट्रिक कार EV Elevate पर बेस्ड हो सकती है, जिसे साल 2026 में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार 2029 तक PF2 प्लेटफॉर्म पर आधारित लॉन्च किया जाएगा, और इसे Elevate से नीचे पोजिशन किया जाएगा।

महंगी हो गई मर्सिडीज बेंज की सवारी! कौन से मॉडल की कीमत में कितनी हुई बढ़ोतरी, पढ़ें खबर

नई दिल्ली। भारतीय बाजार में मर्सिडीज बेंज की ओर से कई सेगमेंट में लग्जरी कारों की बिक्री की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जर्मनी की प्रमुख वाहन निर्माता Mercedes Benz की ओर से अपनी कारों की कीमत में बढ़ोतरी (Mercedes Benz Price Hike) की गई है। निर्माता की ओर से किन कारों की कीमत में कितनी बढ़ोतरी की गई है। इसे कब से लागू किया गया है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

महंगी हुई Mercedes Benz की सवारी

मर्सिडीज बेंज की ओर से भारतीय बाजार में ऑफर की जाने वाली कारों की कीमत बढ़ा दी है। निर्माता की ओर से यह बढ़ोतरी तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। जिसके बाद अब इन कारों को खरीदने के लिए बढ़ी हुई कीमत देनी होगी।

किन मॉडल्स की कीमत बढ़ी

मर्सिडीज बेंज की ओर से पूरे पोर्टफोलियो की कीमत में बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसकी जगह कुछ मॉडल्स की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। जानकारी के मुताबिक ई-क्लास, जीएलए, जीएलसी, सीएलई कैब्रियोलेट मॉडल्स की कीमतों को बढ़ाया गया है।

कितनी हुई बढ़ोतरी

जानकारी के मुताबिक निर्माता की ओर से अपनी कारों की कीमत में 3.70 लाख रुपये तक बढ़ाए गए हैं। यह बढ़ोतरी कैब्रियोलेट में की गई है। जीएलई मॉडल की कीमत में 1.50 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। ई-क्लास के लिए दो लाख रुपये ज्यादा देने होंगे। इसके बाद जीएलए की कीमत में 70 हजार रुपये तक बढ़ाए गए हैं।

क्यों हुई बढ़ोतरी

रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्सिडीज बेंज ने कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए की है क्योंकि रुपये के मुकाबले में यूरो की कीमत लगातार कम ज्यादा हो रही है। जिससे निर्माता की लागत बढ़ रही है। खास बात यह है कि इससे पहले भी निर्माता की ओर से जनवरी में कीमतों को बढ़ाया गया है।

फिर महंगी हो सकती हैं कारें

रिपोर्ट्स के मुताबिक मर्सिडीज बेंज ने कीमतों में बढ़ोतरी इसलिए की है क्योंकि रुपये के मुकाबले में यूरो की कीमत लगातार कम ज्यादा हो रही है। जिससे निर्माता की लागत बढ़ रही है। खास बात यह है कि इससे पहले भी निर्माता की ओर से जनवरी में कीमतों को बढ़ाया गया है।

बाढ़ज़नित हादसों से हानि कैसे रोकें?

योगेंद्र योगी

फरवरी 2021 में उत्तराखंड में एक हिमनद के फटने के कारण बर्फ, हिम और मलबे का स्खलन होने से व्यापक फ्लैश फ्लड उत्पन्न हुआ। भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है और फसलों, घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति के रूप में 1805 करोड़ रुपए मूल्य की हानि का कारण बनती है। सवाल यह है कि आखिर देश के लोग बाढ़ज़नित आपदाओं की मार कब तक झेलते रहेंगे

देश में सरकारी मशीनरी की तंद्रा तब भंग होती है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकारी तंत्र जागने के लिए बड़े हादसे की इंतजार में रहता है। पहले हुए हादसों से सबक सीखने की जरूरत महसूस नहीं की जाती। इसकी प्रमुख वजह है जिम्मेदारी का अभाव। यदि यह जिम्मेदारी तय कर दी जाए कि किसी तरह के हादसे के जिम्मेदारी संबंधित विभागों के अफसरों की होगी और हादसा होने की सूरत में उन्हें सख्त सजा मिलेगी, तभी हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है। अभी मानसून की शुरुआत है। हर साल मानूसन के दौरान देश में बाढ़ जनित हादसों में सैकड़ों लोगों की मौत होती है। भारी बारिश से देश को अरबों रुपयों की सम्पत्ति का नुकसान होता है। जन-धन की इस हानि के लिए किसी की जिम्मेदारी तय नहीं है। आखिर कौन हर साल होने वाले ऐसे हादसों के लिए जिम्मेदार है। हादसा होने के बाद सिर्फ लकीर पीटी जाती है। ऐसे उपाय नहीं किए जाते कि हादसों की पुनरावृत्ति नहीं हो, या फिर इनकी संख्या में कमी लाई जा सके। भारत में बाढ़ से हर साल औसतन 1600 लोगों की मौत हो जाती है। वर्ष 2022 में, बाढ़ के कारण 547 मौतें हुईं। साल 2023 में, उत्तर भारत में बाढ़ के कारण कम से कम 60 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। अभी जारी मानसून में पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 40 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में तेजी से वृद्धि हुई है।

2013-2022 के दशक में हर साल औसतन 8 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 66000 करोड़ रुपए) का नुकसान हुआ। यह 2003-2012 के दशक की तुलना में 125 फीसदी अधिक है, जब यह आंकड़ा 3.8 अरब डॉलर था। वर्ष 2024 के नुकसान की गणना अभी बाकी है, जो इतिहास में भारत का सबसे गर्म साल रहा है। यह वृद्धि बताती है कि या तो प्राकृतिक आपदाएं अधिक बार आ रही हैं, अधिक गंभीर हो गई हैं, या दोनों ही बातें हो रही हैं। 1970 से 2021 तक का डेटा दिखाता है कि समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान में लगातार बढ़ोतरी हुई है। कुछ वर्षों में नुकसान की मात्रा में बड़ी छलांग देखी गई, जो विनाशकारी घटनाओं, जैसे कि बड़े चक्रवातों, बाढ़ या सूखे के कारण हुई। वर्ष 2023 में, भारत को प्राकृतिक आपदाओं से 12 अरब अमेरिकी डॉलर (एक लाख करोड़ रुपए से अधिक) का नुकसान हुआ। यह 2013-2022 के औसत 8 अरब डॉलर से काफी ज्यादा था। स्विस रे की रिपोर्ट के अनुसार, ये बड़े नुकसान उन क्षेत्रों में हुए जहां संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की संख्या ज्यादा है। स्विस रे एक प्रमुख पुनर्बीमा कंपनी है, जो विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट और अध्ययन प्रकाशित करती है। जून 2023 में, चक्रवात बिपरजॉय ने गुजरात के कच्छ जिले में भारी नुकसान पहुंचाया। इसके कारण सौराष्ट्र और कच्छ के सभी बंदरगाह, जैसे कांडला और मुंदरा बंदरगाह, बंद हो गए। तेज हवाओं, भारी बारिश और समुद्री तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई। इस चक्रवात ने महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों को भी प्रभावित किया। दिसंबर 2023 में, चक्रवात मिकाउंग के चलते चेन्नई में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बड़े नुकसान हुए। इसके अलावा जुलाई 2023 में उत्तरी भारत और सिक्किम में आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को बुरी तरह प्रभावित किया। स्विस रे के विश्लेषण में पाया गया कि भारत में पिछले दो दशकों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कुल वार्षिक नुकसान का लगभग 63 फीसदी हिस्सा बाढ़ से जुड़ा हुआ है। इसका कारण भारत की जलवायु और भौगोलिक स्थिति है। भारत में गर्मी का मॉनसून (जून से सितंबर) और पूर्वोत्तर मॉनसून (अक्टूबर से दिसंबर) भारी बारिश लाते हैं, जिससे गंभीर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है।

कुछ बड़ी घटनाओं में 2005 में मुंबई, 2013 में उत्तराखंड, 2014 में जम्मू और कश्मीर, 2015 में चेन्नई और 2018 में केरल की बाढ़ शामिल हैं। साल 2023 में उत्तर भारत की बाढ़ ने भी एक अरब डॉलर से अधिक का नुकसान पहुंचाया। रिपोर्ट कहती है कि नुकसान में वृद्धि के कई कारण हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन प्रमुख है। बढ़ते तापमान से चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ी है। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में बढ़ता निर्माण और आबादी आपदा के समय अधिक नुकसान का कारण बनते हैं। बाढ़ जैसी आपदाओं से सडक़ों, पुलों और सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान होता है। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियां बाधित होती हैं बल्कि यह लोगों की जिंदगी को भी प्रभावित करता है। कुदरती आपदाओं के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घरों का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। इससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं और फिर से निर्माण में भारी खर्च आता है। प्राकृतिक आपदाओं से भारत के कुछ क्षेत्र अधिक प्रभावित हैं। तटीय राज्य, जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल अक्सर चक्रवात और समुद्री तूफानों का सामना करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गंगा के मैदान हर साल बाढ़ से प्रभावित होते हैं। राजस्थान और गुजरात बार-बार सूखे का सामना करते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे हिमालयी क्षेत्र भूकंप और भूस्खलन के लिए संवेदनशील हैं। साथ ही मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहर बाढ़ और जलभराव के लिए अधिक संवेदनशील हैं। वर्ष 2005 की मुंबई बाढ़ और 2015 की चेन्नई बाढ़ भारत की सबसे महंगी प्राकृतिक आपदाओं में से हैं। इनसे क्रमशः 5.3 अरब डॉलर और 6.6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

रिपोर्ट कहती है कि इन घटनाओं से स्पष्ट है कि बेहतर योजना और आपदा प्रबंधन की सख्त जरूरत है। जलवायु परिवर्तन के चलते भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता और बढने की संभावना है। स्विस रे के मुताबिक भारत को आपदा प्रबंधन और तैयारी के लिए बेहतर कदम उठाने होंगे और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा जो आपदाओं का सामना कर सके। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्विस रे की रिपोर्ट में कुछ उपाय भी सुझाए गए हैं, जैसे कि डेटा और प्रभावित केंद्रों की पहचान कर संवेदनशील क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा बनाना होगा। आधुनिक तकनीकों और डेटा का इस्तेमाल कर नुकसान का सटीक आकलन किया जाए। ऐसी बीमा योजनाएं तैयार की जाएं, जो अधिक लोगों तक पहुंच सकें और प्राकृतिक आपदाओं के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकें। फरवरी 2021 में उत्तराखंड में एक हिमनद के फटने के कारण बर्फ, हिम और मलबे का स्खलन होने से व्यापक फ्लैश फ्लड उत्पन्न हुआ। भारत में बाढ़ प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र को प्रभावित करती है और फसलों, घरों एवं सार्वजनिक उपयोगिताओं की क्षति के रूप में 1805 करोड़ रुपए मूल्य की हानि का कारण बनती है। सवाल यह है कि आखिर देश के लोग बाढज़नित आपदाओं की मार कब तक झेलते रहेंगे। हर साल होने वाली मौतें और हजारों करोड़ की सम्पत्ति की बर्बादी आखिर कब थमेगी। सिर्फ प्रकृति को दोष देने से जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लापरवाही और बहानेबाजी का यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा, जब तक सजा का कठोर प्रावधान नहीं होगा।

रक्षा मंत्री ने ठीक किया

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल ठीक किया। ऐसे 'साझा बयान' पर हस्ताक्षर नहीं किए, जो चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ का दस्तावेज था और आतंकवाद पर नजरिया एकतरफा था। 'सीमापार आतंकवाद' पर भारत के नजरिए को नकारा नहीं जा सकता। 'शंघाई सहयोग संगठन' (एससीओ) किसी का निजी संगठन नहीं है। चीन, भारत, पाकिस्तान समेत 10 देशों के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन था, लिहाजा सभी के सरोकार और खासकर आतंकवाद पर उनकी चिंताओं को 'साझा बयान' में शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन भारत के पहलगाम नरसंहार का उल्लेख तक नहीं किया गया। कश्मीर के उस खूबसूरत क्षेत्र में आतंकियों ने पर्यटकों का 'धर्म' पूछा और हिंदू होने पर गोली मार दी। इस तरह 26 मासूम, बेकसूर लोगों की हत्या कर दी गई। उसकी प्रतिक्रिया में भारत को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू करना पड़ा, करीब 170 आतंकियों को ढेर किया गया और उनके अड्डों को 'मिट्टी-मलबा' कर दिया गया। यदि एससीओ आतंकवाद पर कुछ टिप्पणी करना चाहता था, आतंकवाद की निंदा करते हुए उसे खारिज करना चाहता था, तो 'साझा बयान' के दस्तावेज में 'पहलगाम नरसंहार' का जिक्र क्यों नहीं किया गया? यह दोगली रणनीति लगती है। यहीं चीन और पाकिस्तान की आतंकवाद पर नीयत और दृष्टि साफ हो जाती है, लिहाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कलम नीचे रखनी पड़ी और उन्होंने हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। नतीजतन रक्षा मंत्री सम्मेलन 'साझा बयान' के बिना ही सम्पन्न करना पड़ा। भारत के रक्षा मंत्री ने सीमापार आतंकवाद के पनाहगारों, आयोजकों, वित्तपोषकों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराने और उन्हें न्याय के कठघरे तक घसीट कर लाने की बात कही। उन्होंने आतंकवाद की प्रत्येक साजिश और हरकत को आपराधिक और अनुचित करार दिया। एससीओ का उद्देश्य आतंकवाद सरीखे मुद्दों पर साझा रणनीति तय करना है। दस्तावेज में बलूचिस्तान की कथित आतंकी गतिविधियों, जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर आतंकी हमले, को शामिल किया गया है, लेकिन पहलगाम नरसंहार को नजरअंदाज किया गया है। भारत को यह स्वीकार्य नहीं था। दुनिया पाकिस्तान के आतंकी रिकॉर्ड को अच्छी तरह जानती है।

बलूचिस्तान पाकिस्तान का ही हिस्सा है। बलूच आर्मी के लड़ाके, हुकूमत के खिलाफ, विद्रोह कर रहे हैं, लेकिन उसे भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद करार देना खोखला आरोप है। ऐसे संगठन के विमर्श का मजाक उड़ाना है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी पाकपरस्त आतंकियों को बचाता रहा है। यदि वह नापाक गठजोड़ एससीओ में भी जारी रहा है, तो साफ मायने हैं कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय संगठन अपने घोषित मकसद से भटक रहे हैं। क्या चीन के लिए आतंकवाद एक 'रवायती शब्द' है अथवा वह भी आतंकवाद पर गंभीर देश है? एससीओ का रक्षा मंत्री सम्मेलन ऐसा पहला अवसर था, जब आतंकवाद पर पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा किया जा सकता था। हालांकि इसकी उम्मीदें कम ही थीं, क्योंकि चीन पाकिस्तान की पीठ थपथपाता रहा है। एससीओ में भी यही हुआ। भारत जिस आतंकवाद से संत्रस्त रहा है, उसका केंद्र पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान का सदाबहार मित्र चीन है। फिर चीन पाकिस्तान की गर्दन पर पांव रख कर आगे नहीं बढ़ सकता था, जबकि भारत चीन के साथ भी वैश्विक प्रगति के लिए कदम बढ़ाता रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान की हकीकत नहीं देखना चाहता। हकीकत न देखने की गलती पाकिस्तान ने भी की थी, लिहाजा आज वह कर्ज, गरीबी, भुखमरी, महंगाई की जकड़न में है। आतंकवाद का समर्थन करते हुए यह देश अन्य देशों की दया पर आश्रित होता जा रहा है। भारत का रुख सही है। आज की गलाकाट प्रतियोगिता के दौर में भी भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश देने में समर्थ है और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास रखता है। वहां आतंकवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। वैश्विक तौर पर देखें, तो अमरीका, यूरोपीय देश और चीन आतंकवाद पर भारतीय नजरिए के प्रति संवेदनशील नहीं हैं, लेकिन जब अमरीका में 9/11 आतंकी हमला किया गया था, तब भारत को ही याद किया गया था कि इस आतंकवाद से कैसे निपटें! रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद के प्रति 'शून्य सहिष्णुता' का पक्षधर देश है। इसमें आतंकवाद के खिलाफ खुद का बचाव करने का भारत का अधिकार भी शामिल है।

'अच्छे दिन आएंगे तो देखेंगे'

गुरमीत बेदी

मुझे नहीं पता कि अच्छे दिन कब आएंगे। और ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, न ही किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता, जो सुबह उठते ही ये घोषणा कर दूं कि 'अच्छे दिन आ ही गए हैं, बस थोड़ा ध्यान लगाइए, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब बढिया है।' सच कहूं तो मैं उन 'अच्छे दिनों' का ठेका लेकर नहीं बैठा। मेरे जैसे आम आदमी की जिंदगी का असली रोमांच तो इसी में है कि जब फाइल सरकारी दफ्तर में अटक जाए, तो बाबू जी की आंखों में झांकते हुए सौ दो सौ की गांधीजी वाली फोटो टेबल के नीचे सरकाकर अपना काम निकलवा लिया जाए। आप इसे भ्रष्टाचार कह सकते हैं, मैं इसे 'तेज तर्रार बुद्धि' मानता हूं। अब आप ही बताइए, जब किसी अनचाही जगह पर तबादला हो जाता है तो इनसान क्या करे? धरना दे? भूख हड़ताल करे? नहीं जनाब! मैं सीधा अपना लिंक एक्टिवेट करता हूं। पैसे चलते हैं, और तबादला रुकता है। ये सिस्टम है, इसे सिस्टम की तरह ट्रीट कीजिए। भावुक होकर क्या मिलेगा? कोई विरोधी मेरे खिलाफ साजिश रचता है, तो मैं क्या आरती उतारूं उसकी? नहीं साहब, मैं सीधा उसके पुराने पापों की फाइलें बाहर निकालता हूं, कुछ चरित्र हनन की होशियारियां करता हूं, और दो-चार मीडिया वालों को हल्की चाय पर बुला लेता हूं। हिसाब किताब बराबर करना भी एक किस्म की आध्यात्मिकता है। अब आप कहेंगे कि 'नेकी कर और दरिया में डाल', लेकिन मैं वो बेवकूफ नहीं हूं। मैं नेकी करता हूं तो उसका स्क्रीनशॉट रखता हूं, डिजिटल सबूतों के साथ बैंक ऑफ गुडविल में जमा करता हूं, ताकि ज़रूरत पडऩे पर ब्याज सहित वापस मिल जाए। और हां, मैं दो बिल्लियों की लड़ाई में वानर बनकर सिर्फ मध्यस्थता नहीं करता, दोनों से अपना हिस्सा भी तय करवा लेता हूं।

कुछ लोग इसे अवसरवाद कहेंगे, मैं इसे 'जीवन प्रबंधन की कला' कहता हूं। कभी-कभी तो लगता है कि ये 'अच्छे दिन' एक लॉटरी टिकट की तरह हैं, सबको दिखते हैं, पर निकलता किसी का नहीं। लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी लॉटरी तो रोज़ खुलती है, कभी घूस में, कभी जुगाड़ में, कभी चालाकी में। मेरे पड़ोसी रोज़ सरकार को कोसते हैं, सिस्टम पर भडक़ते हैं। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनता हूं, और अगली ही सुबह उनके बिजली के बिल में सुधार करवाने के एवज में उनसे 'धन्यवाद स्वरूप' एक मिठाई का डिब्बा ले आता हूं। कभी किसी मंत्री के चमचे से हाथ मिल जाता है, तो सेल्फी खिंचवा लेता हूं। अगले दिन उसी फोटो को फ्रेम करवा के दीवार पर टांग देता हूं, ताकि आने-जाने वालों को लगे, बड़ी पहुंच वाला बंदा है। मुझे नहीं पता कि वो अच्छे दिन कब आएंगे जिनका सपना लोगों को हर चुनाव में दिखाया जाता है। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब आएंगे, तब की तब देखी जाएगी। तबादला रुकवाने के कितने पैसे लगेंगे, बाबुओं की रिश्वत का नया रेट कार्ड क्या होगा, अस्पतालों में कितने ऑक्सीजन सिलेंडर सरप्लस होंगे और कितने डॉक्टर मिलेंगे, ये सब वक्त आने पर ही पता चलेगा। मेरे लिए तो आज का दिन ही अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूं सिस्टम कैसे चलता है। मैं सिस्टम के साथ बहता हूं, उसके खिलाफ जाकर पत्थर नहीं मारता। अब आप मुझे चाहे अवसरवादी कह लें, सिस्टम का खिलाड़ी, या फिर पुरानी व्यवस्था का उत्पाद, मुझे कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि मैंने समझ लिया है कि आदर्शवाद से पेट नहीं भरता, और ईमानदारी का प्रमाणपत्र रसोई में काम नहीं आता। अच्छे दिन चाहे पांच साल में आएं या पचपन साल में, मेरा तरीका नहीं बदलेगा। क्योंकि जब तक सिस्टम है, तब तक मैं भी हूं। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी स्थिरता है, अच्छे दिन आएंगे, पर मैं तब भी वैसे ही रहूंगा!

राष्ट्रीय वॉलीबाल की कमान वीरेंद्र कंवर के हाथ

भूपिंद्र सिंह

वॉलीबाल खेल जो हिमाचल में सबसे अधिक खेला जाता है, उसे महिला हैंडबाल व कबड्डी की तरह ईमानदार, जुनूनी व मेहनती प्रशिक्षकों की जरूरत है। वीरेंद्र कंवर राज्य ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। हिमाचल खेल जगत वीरेंद्र कंवर को भारतीय वॉलीबाल महासंघ का अध्यक्ष बनने पर बहुत-बहुत बधाई देता है तथा भविष्य में हिमाचल व भारत का वॉलीबाल तरक्की करे, इसके लिए शुभकामनाएं देता है

वॉलीबाल हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल है। जहां राज्य की हर पंचायत व स्कूल में वॉलीबाल की फील्ड में युवा वॉलीबाल खेलते मिल जाएंगे, वहीं पर हिमाचल प्रदेश के खिलाडियों ने समय-समय पर अपनी उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर तक दर्ज करवाई है। हिमाचल वॉलीबाल संघ के गठन में पूर्ण सिंह के प्रयत्नों ने उन्हें हिमाचल वॉलीबाल संघ का प्रथम महासचिव बनाकर राज्य में लोकतंत्र के हिसाब से वॉलीबाल की शुरुआत हुई। बाद में पूर्व मंत्री ठाकुर रामलाल, ठाकुर गुलाब सिंह की श्रृंखला में आज पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर के हाथ अध्यक्ष के रूप में हिमाचल प्रदेश वॉलीबाल संघ की कमान है। दो वर्षों तक तदर्थ रूप से चलने वाले भारतीय वॉलीबाल महासंघ को अंतरराष्ट्रीय वॉलीबाल महासंघ से एफिलिएशन खत्म करने की चेतावनी मिलने के बाद फिर उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर लोकतंत्र को बहाल करने के लिए महासंघ का चुनाव हुआ और नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल कर अब राष्ट्रीय वॉलीबाल की कमान हिमाचल के बेटे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर के हाथ में है।

राष्ट्रीय वॉलीबाल के शीर्ष तक पहुंचने में पूर्व केन्द्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग ठाकुर का आशीर्वाद भी कंवर के साथ रहा है। हिमाचल वॉलीबाल संघ का अध्यक्ष ही जब आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो फिर 'दिव्य हिमाचल' के पाठकों को हिमाचल वॉलीबाल की तब से लेकर अब तक की सच्ची कहानी को जानना जरूरी हो जाता है कि हमारा राज्य इस खेल में कैसे-कैसे फला-फूला है। हिमाचल प्रदेश वॉलीबाल संघ की सक्रियता को आगे ले जाने में महासचिव के रूप में सतीष नाग, स्वर्गीय बीएस ढडवालिया, राष्ट्रीय वॉलीबाल प्रशिक्षक विद्यासागर, हिमाचल खेल विभाग के सेवानिवृत्त अतिरिक्त निदेशक एससी पथिक तथा वर्तमान में सेवानिवृत्त कमांडेंट जागीर सिंह रणधावा का भी अपनी सामथ्र्य अनुसार योगदान रहा है। ये तो खेल प्रशासन की कहानी है, मगर यह सब खेल प्रशिक्षकों व खिलाडियों के प्रयत्नों के बगैर कुछ भी नहीं है। हिमाचल में जहां स्कूल व पंचायत स्तर पर हजारों शारीरिक शिक्षक व पूर्व वॉलीबाल खिलाड़ी प्रारंभिक स्तर पर वॉलीबाल खिलाने की शुरुआत करते हैं, वहीं पर आगे चल कर खिलाडियों को सही प्रशिक्षण की जरूरत महसूस होती है, तो खेल छात्रावासों व खेल विंगों की तरफ खेल प्रतिभा व सुविधा के अनुसार खिलाड़ी अपना-अपना चयन कर लेते हैं। पांच दशक पहले मंडी के सुदूर क्षेत्र संधोल के देशराज शर्मा भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य रहे हैं।

बाद में सेना से हेम सिंह, बीएसएफ से जागीर सिंह रणधावा ने भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन किया है। इनके बाद जुब्बल के धौलटा भाईयों का हिमाचल वॉलीबाल में खूब नाम रहा। देवेंद्र धौलटा के नक्शे कदम पर चल कर चमन धौलटा भारतीय जूनियर टीम का सदस्य रहा। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला के वॉलीबाल प्रशिक्षक दयाल सिंह ने कई खिलाडियों को तराश कर वॉलीबाल को ऊपरी हिमाचल में पहचान दिलाई। देवकीनंदन पांडे व जय सिंह जैसे खिलाड़ी प्रेमियों के प्रयासों से शिमला में वॉलीबाल लोकप्रिय हुआ। पहले शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक, अब कालेज प्रिंसिपल भूपिंदर ठाकुर से भी वॉलीबाल प्रेमियों को आशा है। वे एनआईएस प्रशिक्षक के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के रैफरी भी हैं। वर्तमान में जिला युवा सेवाएं एवं खेल अधिकारी राकेश धौलटा भी वॉलीबाल का बहुत अच्छा राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा है। महिलाओं में राज्य खेल विभाग की वॉलीबाल प्रशिक्षक रविंद्रा वांसटू खिलाड़ी व प्रशिक्षक दोनों ही क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। साई के धर्मशाला में महिला व बिलासपुर में पुरुष वर्ग के लिए छात्रावास बनने के बाद बिलासपुर साई में प्रशिक्षक स्वर्गीय एनके शर्मा के प्रशिक्षण में सुरजीत, मनोज व मदन ने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत की वॉलीबाल में प्रीतम चौहान का प्रशिक्षण के क्षेत्र में बहुत नाम है। धर्मशाला खेल छात्रावास में उनके चार वर्षों तक रहते समय हिमाचल की महिलाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। उसी समय प्रशिक्षक चौहान द्वारा तराशी धर्मशाला साई की खिलाड़ी किन्नौर की बेटी व आजकल राजस्थान पुलिस में निरीक्षक आयुषी भंडारी ने अभी हाल ही में वियतनाम की राजधानी हनोई में हुए एशियन एबीसी चैलेंजर कप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। प्रीतम चौहान आजकल महाराष्ट्र बैंक की महिला टीम को पुणे में ट्रेनिंग दे रहे हैं। हिमाचल सरकार को ऐसे प्रशिक्षकों के बारे में सोचना चाहिए।

प्रशिक्षक विद्यासागर ने कई वर्षों तक पहले प्रशिक्षक व बाद में मुख्य प्रशिक्षक रह कर भविष्य के सैकड़ों प्रशिक्षकों को तैयार किया है। आज भी वे हमीरपुर के भरेड़ी में अपने गांव में रह कर बच्चों के लिए वॉलीबाल अकादमी चलाते हैं। इसी क्षेत्र से एनआईएस पटियाला से वॉलीबाल के मुख्य प्रशिक्षक के पद से सेवानिवृत्त प्रशिक्षक विधिचंद कौशल व साई से सेवानिवृत्त कुलदीप ठाकुर भी हैं। हरियाणा खेल विभाग से उपनिदेशक के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद वॉलीबाल प्रशिक्षक कश्मीर सिंह ठाकुर भी हमीरपुर में ही रह रहे हैं। ये भी भोरंज के ही मूल निवासी हैं। वॉलीबाल खेल जो हिमाचल में सबसे अधिक खेला जाता है, उसे महिला हैंडबाल व कबड्डी की तरह ईमानदार, जुनूनी व मेहनती प्रशिक्षकों की जरूरत है। वीरेंद्र कंवर राज्य ओलंपिक संघ के भी अध्यक्ष हैं। हिमाचल खेल जगत वीरेंद्र कंवर को भारतीय वॉलीबाल महासंघ का अध्यक्ष बनने पर बहुत-बहुत बधाई देता है तथा भविष्य में हिमाचल व भारत का वॉलीबाल तरक्की करे, इसके लिए शुभकामनाएं देता है।

प्रदेश में मानसून और तैयारी की परीक्षा

डा. सिकंदर बंसल

पंचायत स्तर पर आपदा नियंत्रण समितियां बनाई जाएं और उन्हें प्रशिक्षण, उपकरण तथा अधिकार दिए जाएं। विद्यालयों में आपदा शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए

मानसून की दस्तक के साथ ही हिमाचल प्रदेश एक बार फिर आपदा की चपेट में आने को तैयार खड़ा है। पिछले तीन वर्षों- 2022, 2023 और 2024 के आंकड़े स्पष्ट संकेत देते हैं कि पर्वतीय प्रदेश के सामने प्राकृतिक आपदाएं अब अपवाद नहीं, एक नियमित संकट बन चुकी हैं। इस संकट में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या राज्य, जो पहले से आर्थिक दबाव में है, इस चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तैयार है? शासन की नीतियां, आपदा नियंत्रण की व्यवस्था और आम लोगों की जागरूकता- ये तीनों मिलकर ही भविष्य की आपदाओं को कम कर सकते हैं। वर्ष 2022 की वर्षा अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन फिर भी राज्य में 224 भूस्खलन और 142 बाढ़ जैसी घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 156 लोगों की जान गई। लेकिन असली त्रासदी 2023 में आई, जब जुलाई और अगस्त के महीनों में लगातार मूसलधार वर्षा ने शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा जिलों को बुरी तरह प्रभावित किया। कुल 330 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, 10000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ और 1100 से अधिक सडक़ें, 47 पुल तथा दर्जनों विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र नष्ट हो गए। 2024 में यह संकट और बढ़ा। वर्षा पहले से अधिक तीव्र थी और उसका प्रभाव अधिक व्यापक।

शासकीय विवरणों के अनुसार 2024 में कुल 389 लोगों की जान गई, 70 पुल बह गए और 378 मकान पूर्णतः ध्वस्त हो गए। इन आपदाओं ने हिमाचल को सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से हिला कर रख दिया। इन घटनाओं के पीछे सबसे प्रमुख कारणों में भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ हैं। हिमाचल की भौगोलिक बनावट- तीव्र ढलान, नाजुक मिट्टी, नदी घाटियों में अतिक्रमण- भूस्खलन के लिए पहले से ही संवेदनशील है, लेकिन जलवायु परिवर्तन और मानवीय लापरवाहियों ने हालात और भी बिगाड़ दिए हैं। अनियंत्रित निर्माण, पहाडियों की अंधाधुंध कटाई, वन क्षेत्रों का विनाश और जल निकासी की उपेक्षा ने भूमि की पकड़ को कमजोर कर दिया है। जब भारी वर्षा होती है, तो ये ढलान अचानक ढह जाते हैं और निचले क्षेत्रों में भारी तबाही मचाते हैं। वर्षा की तीव्रता और अनियमितता अब सामान्य हो चुकी है। जहां पहले वर्षा कुछ दिनों तक मध्यम होती थी, अब कुछ ही घंटों में महीनों जितनी वर्षा हो जाती है। यह असंतुलन स्पष्ट रूप से पर्यावरणीय संकट का परिणाम है। पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में औसतन 1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिससे वायुमंडलीय अस्थिरता और बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। बादल फटने की दृष्टि से राज्य के कुछ क्षेत्र लगातार अत्यधिक संवेदनशील बने हुए हैं। इनमें किन्नौर के सांगला, चंबा का भरमौर, लाहौल-स्पीति का काजा, कुल्लू की पार्वती घाटी, मंडी का जोगिंद्रनगर और शिमला के रामपुर, रोहड़ू-जुब्बल क्षेत्र प्रमुख हैं। इन इलाकों में वर्ष 2022 से 2024 तक कुल 29 बादल फटने की घटनाएं दर्ज की गईं। यह संख्या दर्शाती है कि अब पर्वतीय गांवों और कस्बों को हमेशा उच्च जोखिम की स्थिति में रहना पड़ेगा। यह सब उस समय हो रहा है, जब राज्य की आर्थिक स्थिति लगातार संकटग्रस्त होती जा रही

है। वर्ष 2025 की पहली तिमाही तक हिमाचल प्रदेश पर कुल ऋण 1.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुका है। केवल ब्याज चुकाने में ही प्रति वर्ष लगभग 9000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

ऐसे में आपदा नियंत्रण के लिए अलग से मजबूत और लचीला कोष बनाना एक बड़ी चुनौती है। फिर भी प्रश्न यह है- क्या हर संकट के समय केवल संसाधनों की कमी को ही दोष देना उचित है? इसका उत्तर स्पष्ट है- नहीं। सीमित साधनों में भी बेहतर योजना, पूर्व तैयारी, जन सहयोग और तकनीकी उपयोग के माध्यम से आपदा के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, गांव स्तर पर चेतावनी प्रणाली की स्थापना, पूर्वाभ्यास (मॉक ड्रिल), सामूहिक राहत समूहों का निर्माण, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की सुदृढ़ता- ये सब अपेक्षाकृत कम लागत में संभव हैं, परंतु प्रशासनिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इन पर गंभीर कार्य नहीं हो पाता। जहां तक केंद्र सरकार की सहायता का प्रश्न है, प्रतिवर्ष हिमाचल को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष और प्रधानमंत्री राहत कोष से कुछ धनराशि प्राप्त होती है। 2023 में केंद्र ने हिमाचल को 450 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सहायता दी थी, जबकि राज्य ने 1500 करोड़ रुपए की मांग की थी। 2024 में भी तत्काल राहत के रूप में 400 करोड़ रुपए मिले, लेकिन पुनर्निर्माण के लिए कोई पृथक विशेष पैकेज नहीं आया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सहायता तो मिलती है, परंतु वह वास्तविक आवश्यकता की तुलना में बहुत कम होती है। हर वर्ष वर्षा ऋतु के साथ ही हिमाचल का खजाना खाली होने लगता है, सडक़ें टूटती हैं, पुल बहते हैं, विद्यालय और अस्पताल बंद हो जाते हैं और पर्यटन उद्योग को गहरा आघात पहुंचता है। 2023 में आई आपदा के कारण केवल पर्यटन को ही लगभग 2000 करोड़ रुपए की क्षति हुई। बुकिंग में 50 प्रतिशत तक गिरावट आई और हजारों लोगों की आजीविका पर संकट मंडराने लगा। 2024 में भी यह स्थिति दोहराई गई।

अब 2025 में भी मानसून के साथ बुकिंग रद्द होने लगी हैं। ऐसे में राज्य की पहले से ही कमजोर अर्थव्यवस्था पर मानसून हर वर्ष एक और घाव बनकर आता है। किन्तु इस निराशाजनक स्थिति के भीतर भी समाधान छिपा हुआ है- यदि तैयारी वैज्ञानिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से की जाए। सबसे पहले, संवेदनशील क्षेत्रों की भौगोलिक और भूगर्भीय नक्शे के आधार पर पहचान की जाए, ताकि निर्माण केवल सुरक्षित क्षेत्रों में हों। नगरीय नियोजन में जल निकासी, हरित पट्टियां और जलधाराओं की रक्षा को अनिवार्य किया जाए। पंचायत स्तर पर आपदा नियंत्रण समितियां बनाई जाएं और उन्हें प्रशिक्षण, उपकरण तथा अधिकार दिए जाएं। विद्यालयों में आपदा शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाए। और सबसे आवश्यक, शासन तंत्र को वर्ष भर सजग रहना होगा, केवल आपदा आने पर नहीं। राज्य सरकार को चाहिए कि वह पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष सहायता कोष की मांग केंद्र से करे। यह कोष आपदा प्रबंधन और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए पृथक रूप से स्थापित किया जाए। इसके साथ-साथ निर्माण कार्यों में स्थानीय इंजीनियरों की भूमिका, निर्माण कंपनियों की जवाबदेही और सामाजिक निगरानी को भी सशक्त किया जाना चाहिए। बेहतर योजना से नुकसान को कम किया जा सकता है।

बढ़ रहा सोशल मीडिया का प्रभाव-जिम्मेदारी और जागरूकता जरूरी (30 जून विश्व सोशल मीडिया दिवस पर विशेष आलेख)

30 जून को 'विश्व सोशल मीडिया' दिवस मनाया जाता है। आज के युग में सोशल मीडिया का बहुत महत्व है। यह सोशल मीडिया(फेसबुक, व्हाट्स एप, ट्विटर, इंस्टाग्राम) ही है जिसके कारण आज दुनिया श्रिंक हो गई है। यह आपस में लोगों को जोड़ने, विचारों का आदान-प्रदान करने तथा समाज और देश में पाज़ीटिव बदलाव लाने का एक सशक्त और शानदार माध्यम है। वास्तव में, यह दिन सोशल मीडिया के हमारे जीवन में महत्व को पहचानने और इसका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। पाठकों को जानकारी देना चाहूंगा कि वर्ष 1997 में, पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'सिक्सडिग्रीज़' लॉन्च किया गया था, और वर्ष 2010 में मैशेबल द्वारा विश्व सोशल मीडिया दिवस की शुरुआत की गई थी। गौरतलब है कि एंड्रयू वेनरिच द्वारा स्थापित, इस वेबसाइट पर उपयोगकर्ता अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध कर सकते थे और इसमें प्रोफ़ाइल, बुलेटिन बोर्ड और स्कूल संबद्धता जैसी सुविधाएँ थीं। हालांकि, दस लाख से ज़्यादा उपयोगकर्ताओं के बावजूद वर्ष 2001 में इसे बंद कर दिया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पहला आधुनिक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 2002 में फ्रेंडस्टर था। इसी प्रकार से लिंक्डइन, पहला व्यवसाय-केंद्रित सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 2003 में लॉन्च किया गया था। माईस्पेस 2004 में लॉन्च हुआ, उसी साल फ़ेसबुक(कैमब्रिज, मैसाचुसेट्स में स्थापित इस वेबसाइट के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग) भी लॉन्च हुआ। बाद में वर्ष 2006 तक माईस्पेस दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म बन गया।यूट्यूब(विडियो वेबसाइट जिसका जन्म कैलिफोर्निया के सैन मेटियो में हुआ) ने वर्ष 2005 में और उसके बाद ट्विटर ने वर्ष 2006 में सीमित अक्षरों वाला अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया।इंस्टाग्राम साल 2010 में लॉन्च हुआ और इसने तेज़ी से विकास किया। बहरहाल, आज दिन-ब-दिन सोशल मीडिया की लोकप्रियता बढ़ती ही चली जा रही है लेकिन यह बहुत ही दुखद है कि तकनीक का आज मिसयूज(ग़लत उपयोग) किया जा रहा है। आज सोशल मीडिया पर डेटा चोरी किया जाता है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। फर्जी खबरों को लेकर विवाद होता है। ऐसी ऐसी सामग्री या कंटेंट का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है, जिससे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य(अवसाद और चिंता के कारण) पर बहुत बुरा असर पड़ता है। साइबर बुलिंग(एक दूसरे को धमकाना, परेशान करना) की समस्या जैसे आज आम हो चली है ।सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग वास्तविक दुनिया के रिश्तों को कम कर सकता है, जिससे सामाजिक अलगाव हो सकता है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन को भी प्रभावित करता है। वास्तव में आज सोशल मीडिया पर नकारात्मक(नेगेटिव), ग़लत और भ्रामक सूचनाओं, जानकारियों से बचने की जरूरत है। यह ठीक है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आजादी सबको प्रदान की गई है, लेकिन पिछले कुछ समय से देश और समाज के कुछेक लोगों ने तकनीक और अभिव्यक्ति की आजादी का बहुत ही ग़लत उपयोग किया है। विशेषकर यू ट्यूबर्स-नैतिकता और मर्यादा को तांक पर रखकर कुछ भी ऊल-जुलूल इन माध्यमों पर बेरोकटोक परोस रहे हैं। यू-ट्यूबर्स और फेसबुक पर कंटेंट प्रस्तुतीकरण का तरीका बहुत ही अजीबोगरीब व ग़लत हो गया है। फेसबुक, यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा लाइक्स, शेयर और कमेंट्स पाने के लिए यूट्यूबर्स और फेसबुक संचालक अपनी मर्यादाएं भूल रहें हैं और उन्हें समाज और देश से कोई भी सरोकार नहीं रहा है। बहरहाल, पाठक जानते हैं कि यू-ट्यूब और फेसबुक सार्वजनिक मंच हैं और आज संपूर्ण विश्व इन मंचों से जुड़ा हुआ है। कोई भी पोस्ट इन मंचों पर पोस्ट की जाती है तो उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं, इसलिए यह बहुत ही जरूरी है कि इन मंचों पर प्रामाणिक और विश्वसनीय जानकारी ही पोस्ट की जाए और देश की सुरक्षा का हमेशा ध्यान रखा जाए। बहरहाल, कहना ग़लत नहीं होगा कि सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव हैं। सोशल मीडिया संचार और सामाजिकीकरण को बढ़ावा देता है। यह विभिन्न सामाजिक मुद्दों, राजनीतिक आंदोलनों और शैक्षिक अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। यह सोशल मीडिया ही है जो रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति को अवसर प्रदान करता है। यह व्यावसायिक अवसरों को जन्म दे सकता है। सामाजिक परिवर्तन लाने की अभूतपूर्व क्षमताएं रखता है ।सोशल मीडिया संकट के समय में लोगों को समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त करने, दूसरों के साथ जुड़ने और अकेलेपन को कम करने में मदद करता है। सीखने के अवसरों के साथ ही सोशल मीडिया व्यक्तिगत विकास में भी सहायक सिद्ध होता है। बस जरूरत इस बात की है कि हम तकनीक का प्रयोग पूरी जिम्मेदारी, जागरूकता और संतुलित तरीके से करें। तभी वास्तव में इस दिवस को मनाने की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

-सुनील कुमार महला

जल की बूंद-बूंद पर संकट: नीतियों के बावजूद क्यों प्यासी है भारत की धरती?

भारत दुनिया की 18% आबादी और मात्र 4% ताजे जल संसाधनों के साथ गंभीर जल संकट का सामना कर रहा है। भूजल का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, असंतुलित खेती, और जलवायु परिवर्तन इसके प्रमुख कारण हैं। सरकारी योजनाओं और नीतियों के बावजूद कार्यान्वयन और जनभागीदारी की कमी से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाना, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना, जल की कीमत तय करना, और पुनर्चक्रण को अनिवार्य बनाना समय की मांग है। जब तक नीति, व्यवहार और चेतना एकसाथ नहीं बदलते, तब तक जल संकट भारत के भविष्य को चुनौती देता रहेगा।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

भारत की धरती पर जल का संकट एक ऐसी विडंबना बन चुका है, जिसे देखकर हैरानी होती है कि इतनी योजनाओं, घोषणाओं और नीतियों के बावजूद यह देश बूंद-बूंद के लिए क्यों तरस रहा है। जब कोई देश दुनिया की 18% जनसंख्या को समेटे हुए हो और उसके पास केवल 4% ताजे जल संसाधन हों, तो संकट की आशंका तो बनती है, पर यदि यही देश दशकों से जल संरक्षण और जल प्रबंधन की योजनाओं का ढोल पीटता हो और फिर भी सूखा, प्यास, और जलजनित बीमारियाँ उसके हिस्से में आएं — तो यह केवल प्राकृतिक संकट नहीं, यह नीति, प्रशासन और नागरिक चेतना की सामूहिक असफलता है।

भारत में पानी की स्थिति को अगर आंकड़ों की भाषा में समझें, तो भयावहता साफ़ दिखाई देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा भूजल उपभोक्ता है — लगभग 25% भूजल अकेले भारत निकालता है। 11% से अधिक भूजल खंड 'अत्यधिक दोहित' यानी over-exploited की स्थिति में हैं। दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे 21 प्रमुख शहरों के 2030 तक भूजल समाप्त होने की चेतावनी दी जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर, 70% जल स्रोत प्रदूषित हैं। फ्लोराइड, आर्सेनिक, नाइट्रेट और भारी धातुओं से दूषित यह जल 23 करोड़ से अधिक लोगों को प्रभावित कर रहा है। हर साल लगभग 1 लाख मौतें सिर्फ जलजनित बीमारियों से होती हैं — यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, यह हमारी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है।

पानी का यह संकट केवल ग्रामीण इलाकों या गरीबों तक सीमित नहीं है। 2019 में जब चेन्नई जैसे आधुनिक शहर को "Day Zero" का सामना करना पड़ा और जल ट्रेनें चलानी पड़ीं, तब यह साफ हो गया कि यह समस्या अब दरवाज़े पर नहीं, घर के भीतर आ चुकी है। और फिर भी हम इसे मौसमी समस्या मानकर हर बार भूल जाते हैं। सवाल यह है कि नीतियाँ तो बनीं — राष्ट्रीय जल नीति (2012), जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना, नमामि गंगे, जल शक्ति अभियान — पर फिर भी पानी का स्तर क्यों गिरता जा रहा है? जवाब सरल है — हमारी नीतियाँ ज़मीन पर नहीं उतरतीं, और हमारे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता।

आज भी देश के अधिकांश किसान पानी की फिजूलखर्ची करने वाली फसलों की खेती करते हैं। पंजाब और हरियाणा जैसे जल-संकटग्रस्त राज्य में धान और गन्ने की खेती केवल इसलिए होती है क्योंकि सरकार MSP और मुफ्त बिजली देती है। नतीजा — भूजल का तेज़ी से दोहन, खेतों का क्षरण, और जल स्रोतों का खत्म हो जाना। दूसरी ओर, ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकलर जैसे आधुनिक जल संरक्षण उपायों की पहुंच केवल 9% खेतों तक ही सीमित है। किसान जानते हैं, पर अपनाते नहीं — क्योंकि नीति और व्यवहार में दूरी है।

शहरों की बात करें तो पाइपलाइन से लेकर टंकी तक, हर जगह लीकेज और बर्बादी का आलम है। स्मार्ट मीटरिंग अभी भी अधिकांश नगरपालिकाओं के लिए नया शब्द है। पुनः उपयोग (recycling) और वर्षा जल संचयन (rainwater harvesting) जैसे उपाय कहीं-कहीं दिखते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से अपनाए नहीं जाते।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि जल संकट को अब भी केवल 'प्राकृतिक समस्या' समझा जाता है। जबकि यह एक स्पष्ट रूप से 'नीतिगत और नैतिक' संकट है। जब तक यह दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तब तक कोई भी योजना सफल नहीं होगी।

अब समय आ गया है कि भारत पानी को "मुफ्त संसाधन" मानना बंद करे और उसे "जीवन मूल्य" की तरह देखे। इसके लिए कुछ गहन और ठोस सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले, पानी की कीमत तय होनी चाहिए — चाहे वह पीने का हो, या सिंचाई का। मुफ्त पानी की संस्कृति ने उपभोग को बर्बादी में बदल दिया है। जल का मूल्य निर्धारण सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय विवेक के बीच संतुलन साध सकता है।

दूसरा, सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को केवल योजना पत्रों से निकालकर ज़मीनी हकीकत बनाना होगा। इसके लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सस्ती उपलब्धता, और स्थानीय स्तर पर सहायता तंत्र बनाना होगा। तीसरा, भूजल का प्रबंधन केवल सरकार का नहीं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों का भी कर्तव्य होना चाहिए। अटल भूजल योजना को इस दिशा में सफल मॉडल के रूप में बढ़ाया जा सकता है।

चौथा, किसानों को केवल फसल बीमा या सब्सिडी नहीं, जल आधारित फसल मार्गदर्शन की ज़रूरत है। यह तभी होगा जब MSP का ढांचा जल संरक्षण के अनुकूल फसलों को बढ़ावा देगा। देश को ऐसे नीतिगत हस्तक्षेपों की ज़रूरत है जो किसान की आय भी बढ़ाएं और पानी की बचत भी करें।

पाँचवां, शहरों में जल पुनर्चक्रण अनिवार्य किया जाए। जो नगर पालिकाएं wastewater को recycle नहीं करतीं, उन्हें दंड और प्रोत्साहन दोनों के माध्यम से बदला जाए। बड़े भवनों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य हो, और इसके अनुपालन की निगरानी की जाए।

छठा, बच्चों के स्कूली पाठ्यक्रम में जल संरक्षण को केवल पर्यावरण अध्याय के रूप में न पढ़ाया जाए, बल्कि व्यवहार परिवर्तन के रूप में सिखाया जाए। यदि अगली पीढ़ी जल को 'कीमती' माने, तो आज की प्यास भविष्य की सूखी धरती को बचा सकती है।

सातवां, जल संरक्षण को 'जन आंदोलन' बनाना होगा — जैसा प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था। लेकिन यह आह्वान केवल भाषणों में नहीं, बजट और प्रशासनिक प्रतिबद्धता में दिखना चाहिए। जल शक्ति मंत्रालय को केवल नल जोड़ने वाला मंत्रालय नहीं, जल नीति, जल शिक्षा और जल चेतना का नेतृत्व करना होगा।

साथ ही, निजी क्षेत्र की भूमिका को भी समझना और बढ़ाना होगा। जल एटीएम, पाइपलाइन प्रबंधन, स्मार्ट मीटरिंग, और जल पुनर्चक्रण जैसी सेवाओं में PPP मॉडल को बढ़ावा देकर न केवल निवेश लाया जा सकता है, बल्कि तकनीकी नवाचार भी हो सकते हैं।

और सबसे महत्वपूर्ण — हमें यह समझना होगा कि जल संकट केवल वैज्ञानिकों और नौकरशाहों का विषय नहीं है। यह आम नागरिक का संकट है। हर घर, हर हाथ को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि पानी को बर्बाद नहीं किया जाएगा, और हर बूंद का सम्मान होगा।

जलवायु परिवर्तन के इस युग में, जब बारिश की मात्रा अनिश्चित हो गई है, और हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं — हमें जल को 'अनंत' नहीं, बल्कि 'सीमित और नाजुक' संसाधन मानना होगा। भारत की सांस्कृतिक परंपरा में जल को देवता का दर्जा मिला है — लेकिन विडंबना यह है कि आज वही जल नदियों में मल-मूत्र के रूप में बह रहा है, या गंदे नालों से होकर भूजल में जहर घोल रहा है।

इसलिए आज का भारत केवल 'जल संकट' नहीं झेल रहा, बल्कि वह अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जल संकट में डूबा भारत, विकास के हर मोर्चे पर कमजोर पड़ता जाएगा — चाहे वह स्वास्थ्य हो, कृषि, उद्योग या सामाजिक समरसता।

अंततः यही कहा जा सकता है कि जल संकट केवल पानी की समस्या नहीं है — यह व्यवस्था, संस्कृति, शिक्षा और नीयत की भी परीक्षा है। यदि हमने अब भी नहीं संभला, तो इतिहास गवाह रहेगा कि हमने एक ऐसे संसाधन को खो दिया, जो जीवन का मूल था, और जिसकी एक-एक बूंद सोने से भी महंगी थी।

अब वक्त आ गया है — नीतियों की बौछार से बाहर निकलकर बूंद-बूंद बचाने के व्यवहारिक आंदोलन को अपनाने का। क्योंकि आने वाले वर्षों में 'जल' ही 'राजनीति', 'आर्थिक ताकत' और 'सामाजिक न्याय' का सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है।

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस: संसदों के अंतर्मंथन का क्षण

[लोकतंत्र का संस्कारगृह – संसद और सतत समावेश]

जब हम किसी राष्ट्र की आत्मा को समझने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने उसकी संसद की छवि उभरती है—वह पवित्र मंच, जहाँ जनता की आकांक्षाएँ, चिंताएँ और अधिकार एक स्वर में गूंजते हैं। संसद केवल कानूनों का कारखाना नहीं, बल्कि लोकतंत्र का वह जीवंत हृदय है, जो हर नागरिक की धड़कनों को प्रतिबिंबित करता है। इस जीवंतता को वैश्विक स्तर पर और सशक्त करने के लिए हर साल 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल संसदों की उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि उनके दायित्वों, चुनौतियों और भविष्य की दिशा में गहन चिंतन का अवसर है। यह एक ऐसा आह्वान है, जो संसदों को याद दिलाता है कि वे केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि जनता की आवाज़, विश्वास और उम्मीदों का प्रतीक हैं।

इस महत्वपूर्ण दिवस की शुरुआत 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के माध्यम से हुई, जब 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस के रूप में मान्यता दी गई। यह तारीख संयोगवश 1889 में स्थापित इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (आईपीयू) की स्थापना की वर्षगांठ से भी जुड़ी है। आईपीयू वह वैश्विक संगठन है, जिसने 136 साल पहले संसदों को एक मंच पर लाकर वैश्विक संवाद, शांति और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की नींव रखी। इसका नारा—"लोकतंत्र के लिए, सभी के लिए" और उद्देश्य "संसदों के माध्यम से विश्व शांति और विकास के लिए हर आवाज़ को सुनना" आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 2025 में इस दिवस की थीम "संसद और सतत विकास लक्ष्य: लैंगिक समानता और समावेशिता" न केवल समय की मांग है, बल्कि लोकतंत्र की सच्ची आत्मा को उजागर करती है। यह थीम हमें याद दिलाती है कि कोई भी लोकतंत्र तब तक पूर्ण नहीं हो सकता, जब तक उसमें हर वर्ग—महिलाएँ, युवा, हाशिए पर पड़े समुदाय, और सामाजिक रूप से उपेक्षित लोग—की समान भागीदारी सुनिश्चित न हो।

आज विश्व संयुक्त राष्ट्र के 2030 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की ओर तेज़ी से बढ़ रहा है। इन 17 लक्ष्यों में लैंगिक समानता (एसडीजी-5) और मज़बूत, समावेशी संस्थानों का निर्माण (एसडीजी-16) संसदों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक स्तर पर संसदों में महिलाओं की भागीदारी अभी भी केवल 26% है (आईपीयू, 2023), जबकि भारत में यह आंकड़ा और भी कम, लगभग 14.4% (लोकसभा, 2024) है। यह असंतुलन न केवल लैंगिक समानता के लिए चुनौती है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाता है। संसदें नीतियां बनाती हैं, संसाधनों का आवंटन करती हैं और सरकार को जवाबदेह बनाती हैं। लेकिन अगर इन नीतियों में आधी आबादी की आवाज़ शामिल नहीं है, तो क्या यह लोकतंत्र वास्तव में "सभी के लिए" है?

भारत, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इस संदर्भ में एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारतीय संसद, लोकसभा और राज्यसभा, करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं का केंद्र है। यह वह मंच है, जहाँ 1.4 अरब लोगों की विविधता को एक स्वर में ढाला जाता है। लेकिन इस विविधता को प्रतिबिंबित करने के लिए संसद को और अधिक समावेशी होना होगा। उदाहरण के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इसका पूर्ण कार्यान्वयन अभी बाकी है। इसी तरह, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे आदिवासियों, दलितों, और एलजीबीटीक्यू+ समुदाय को संसद में अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, लेकिन संसद में युवा सांसदों की संख्या केवल 12% के आसपास है। यह असंतुलन न केवल नीतियों को प्रभावित करता है, बल्कि युवाओं के बीच राजनीतिक संस्थानों के प्रति विश्वास को भी कम करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें उन मूलभूत सवालों से रूबरू कराता है, जो अक्सर संसदीय बहसों के शोर में दब जाते हैं। क्या संसदें जनता के सबसे ज़रूरी मुद्दों को प्राथमिकता दे रही हैं? क्या वे लैंगिक भेदभाव, सामाजिक असमानता और पर्यावरणीय संकट जैसे मुद्दों पर ठोस कदम उठा रही हैं? आईपीयू की 2022 की वैश्विक संसदीय रिपोर्ट के अनुसार, केवल 40% संसदों ने ही सतत विकास लक्ष्यों को अपनी नीतियों में स्पष्ट रूप से शामिल किया है। यह आंकड़ा चेतावनी देता है कि संसदों को अपनी भूमिका को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाना होगा। भारत में, उदाहरण के लिए, संसद ने जलवायु परिवर्तन (एसडीजी-13) और शिक्षा (एसडीजी-4) जैसे क्षेत्रों में कई नीतियां बनाई हैं, लेकिन उनकी निगरानी और कार्यान्वयन में कमी दिखती है।

संसदों की जवाबदेही और पारदर्शिता लोकतंत्र की नींव है। आईपीयू के अनुसार, विश्व की 80% संसदें अब डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर रही हैं, जैसे कि ऑनलाइन सत्र, ई-वोटिंग, और नागरिक संवाद मंच। भारत में भी डिजिटल संसद पहल के तहत संसद के सत्रों को डिजिटल रूप से प्रसारित किया जा रहा है, लेकिन नागरिकों की सीधी भागीदारी अभी भी सीमित है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि संसदें न केवल नीतियां बनाएं, बल्कि नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करें। उदाहरण के लिए, न्यूज़ीलैंड और कनाडा जैसे देशों में "संसदीय ओपन डे" जैसे आयोजन होते हैं, जहाँ आम लोग संसद में जाकर अपने सांसदों से मिल सकते हैं। भारत में भी इस तरह की पहल लोकतंत्र को और जीवंत बना सकती हैं।

इस दिवस का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह संसदों को आत्म-मूल्यांकन का अवसर देता है। क्या संसदें वास्तव में समावेशी हैं? क्या वे बदलते समय के साथ तालमेल बिठा रही हैं? आईपीयू की एक रिपोर्ट के अनुसार, विश्व की केवल 20% संसदों में ही लैंगिक समानता और समावेशिता के लिए विशेष समितियाँ हैं। भारत में, हालाँकि संसद में महिला सशक्तीकरण समिति जैसी संरचनाएँ हैं, लेकिन इनका प्रभाव अभी व्यापक नहीं हुआ है। यह समय है कि संसदें न केवल कानून बनाएं, बल्कि स्वयं को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और जवाबदेह बनाने के लिए नवाचार करें

नागरिकों की भूमिका भी इस दिन उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र केवल संसद तक सीमित नहीं है; यह जनता की जागरूकता और भागीदारी से जीवित रहता है। हम कितनी बार अपने सांसदों से सवाल पूछते हैं? कितनी बार संसद के सत्रों पर ध्यान देते हैं? भारत में, आरटीआई (सूचना का अधिकार) जैसे उपकरणों ने नागरिकों को सशक्त किया है, लेकिन संसदीय कार्यवाहियों में उनकी भागीदारी अभी भी न्यूनतम है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि लोकतंत्र एक दोतरफा प्रक्रिया है, संसद को जनता के प्रति जवाबदेह होना होगा, और जनता को संसद के प्रति जागरूक।

30 जून केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है—एक संकल्प कि संसदें केवल सत्ता के गलियारों में गूंजने वाली आवाज़ें न बनें, बल्कि समाज के हर कोने तक समानता, न्याय और विकास की गूंज पहुँचाएँ। जब संसदें हर नागरिक की आवाज़ को सुनेंगी—चाहे वह एक महिला हो, एक युवा हो, या समाज के हाशिए पर खड़ा व्यक्ति—तब ही लोकतंत्र एक नारा नहीं, बल्कि एक जीवनशैली बनेगा। यह दिवस हमें यह विश्वास दिलाता है कि संसदें केवल कानून बनाने वाली इमारतें नहीं, बल्कि वे मंदिर हैं, जहाँ मानवता की आकांक्षाएँ आकार लेती हैं। इस 30 जून को हम संकल्प लें कि हमारी संसदें न केवल सशक्त होंगी, बल्कि संवेदनशील, समावेशी और सतत विकास की दिशा में मार्गदर्शक भी बनेंगी। यही लोकतंत्र की सच्ची जीत होगी।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

रूस की जंग में फंसे भारतीय नागरिक: वैश्विक आक्रोश और भारत की चुप्पी

126 भारतीय नागरिकों को सुनहरे सपनों का झांसा देकर रूस भेजा गया जहां उन्हें जबरन रूसी सेना में भर्ती कर युद्ध में झोंक दिया गया। यह त्रासदी अब केवल भारत तक सीमित नहीं रही बल्कि बेरोज़गारी, मानव तस्करी और वैश्विक भू-राजनीति का खतरनाक मेल बन चुकी है।

27 जून को नई दिल्ली के एआईसीसी मुख्यालय, इंदिरा भवन में कांग्रेस सांसद और पंजाब प्रदेश अध्यक्ष श्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस मुद्दे को सार्वजनिक किया। उनके साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद थे जिनके युवा सदस्य नौकरी के बहाने रूस भेजे गए और फिर लौट नहीं सके।

'जालसाज़ी की सच्चाई और ज़मीनी हकीकत'

'द हिंदू' अखबार की फरवरी 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय युवाओं को ₹आर्मी सिक्योरिटी हेल्परऱ की नौकरी का झांसा देकर प्रति माह 1.95 लाख रुपये सैलरी और बोनस का वादा किया गया। असलियत में उन्हें रूसी सेना में जबरन भर्ती कर दिया गया और युद्ध में भेज दिया गया। कई को धमकाया गया कि इंकार करने पर जेल भेज दिया जाएगा।

सबसे दर्दनाक कहानी पंजाब के मंदीप कुमार की है, जो विकलांग हैं, फिर भी उन्हें पीट-पीटकर स्नाइपर की ट्रेनिंग दी गई। मंच पर परिवारों ने अपने बेटों की रूसी सेना की वर्दी में तस्वीरें दिखाईं जो इस शोषण की भयावहता उजागर करती हैं।

126 में से लगभग 100 भारतीय किसी तरह वापस लौटे हैं, कई घायल और मानसिक रूप से टूट चुके हैं। 14 भारतीय अब भी लापता हैं — जिनमें 9 उत्तर प्रदेश, 3 पंजाब, 1 महाराष्ट्र और 1 जम्मू-कश्मीर के हैं।

राजा वड़िंग ने कहा, ₹यह केवल पंजाब नहीं, पूरे देश की शर्मनाक स्थिति है। अमृत काल में हमारे युवा बेरोजगारी और धोखाधड़ी के कारण युद्ध क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और सरकार चुप बैठी है।₹

राजा वड़िंग ने मोदी सरकार से सवाल किया कि-

- _क्या भारत सरकार रशिया से पूछेगी कि बिना अनुमति के हमारे लोगों को वहां की सेना में भर्ती क्यों किया गया ?_
- _क्या भारत सरकार ने हमारे लोगों को वापस लाने का कोई प्रयास किया है?_
- _हमारे जो लोग आज भी लापता हैं, क्या सरकार ने उनकी कोई मदद की है?_
- _क्या सरकार ने उन एजेंटों के ऊपर कोई कार्रवाई की है, जो रशिया की सरकार से मिले हुए हैं और यहां से युवाओं को लेकर वहां जा रहे हैं।

वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी और भारत की स्थिति

संयुक्त राष्ट्र की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि रूस विकासशील देशों के नागरिकों को धोखे से सैन्य भर्ती कर यूक्रेन युद्ध में झोंक रहा है।

एक अंतरराष्ट्रीय जांच

iStories और अन्य संगठनों द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय जांच में खुलासा हुआ कि 2025 की शुरुआत तक 48 देशों के 1,500 से अधिक विदेशी नागरिक जिनमें सैकड़ों दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी शामिल हैं, इसी तरह धोखा खाकर रूस में भर्ती हुए।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, हर साल करीब 2.9 करोड़ भारतीय विदेश में रोजगार की तलाश में जाते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने 2024 में माना कि 1,200 से अधिक भारतीय ठग एजेंटों के शिकार बने लेकिन 2020 से अब तक केवल 300 मामलों में ही सजा हो पाई। यह केवल कानून व्यवस्था नहीं बल्कि नीतिगत विफलता भी दर्शाता है।

'अंतरराष्ट्रीय आलोचना और भारत की धीमी प्रतिक्रिया'

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2024 की रिपोर्ट में रूस की इस ज़बरन भर्ती को ₹मानवाधिकारों का घोर उल्लंघनऱ बताया। सैकड़ों भारतीयों और अन्य विदेशियों को बिना प्रशिक्षण के युद्ध में झोंक दिया गया।

फिर भी भारत की प्रतिक्रिया बेहद धीमी रही। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा में इन भारतीयों का कोई ज़िक्र नहीं हुआ।

राजा वड़िंग ने सवाल उठाया, 'विदेश में भारतीयों की जान की कीमत क्या है? तस्करों का नेटवर्क बंगाल, पंजाब समेत पूरे देश में फल-फूल रहा है और सरकार मौन है।'

परिवारों की टूटती उम्मीदें

मंदीप कुमार के भाई जगदीप सिंह बोले, '18 महीने से दूतावास के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। क्या हमारी सरकार केवल अमीरों के लिए है?'

खुशबू यादव, जिनके भाई योगेंद्र यादव एक साल से लापता हैं, बोलीं, 'रोज़ माता-पिता की हालत बिगड़ती जा रही है, क्या सरकार सुन रही है?'

राजा वड़िंग ने भरोसा दिया कि जरूरत पड़ी तो वे खुद इन परिवारों को रूस भेजने का खर्च उठाएंगे लेकिन असली जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है।

'अमृत काल या खोखले वादे?'

'दो करोड़ नौकरियों का वादा हुआ था, अगर वह पूरा होता तो हमारे युवा जान जोखिम में डालकर विदेश क्यों जाते?' वड़िंग ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया।

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, रूस में खुद की सैन्य भर्ती में 80% तक गिरावट आई है, इसलिए वे विदेशियों को मोटे वेतन, बोनस और नागरिकता का लालच देकर भर्ती कर रहे हैं।

'भारत के सामने अहम चुनौती'

पूरी दुनिया रूस के सैन्य विस्तार और विदेशी नागरिकों के शोषण पर नज़र रख रही है। भारत को तय करना है कि वह अपने नागरिकों को बचाएगा, मानव तस्करी पर लगाम लगाएगा या आर्थिक विवशता और वैश्विक युद्ध में अपने युवाओं को खो देगा।

14 लापता भारतीयों का कोई अता-पता नहीं। उनके परिवार हर मंच पर गुहार लगा चुके हैं। अब देखना है कि सरकार इन आवाज़ों को सुनेगी या ये भी सन्नाटे में गुम हो जाएंगी।

-ओंकारेश्वर पांडेय

रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से प्रभू पहुंचे गुड़िचा के आंगन में

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची , राजधानी रांची समुचा झारखंड कभी कलिंग था जहां राजधानी रांची में विगत 333 वर्षों से जगन्नाथ जी की रथयात्रा का आयोजन इस क्षेत्र का मुख्य धार्मिक आकर्षक का केंद्र माना जाता है . कल रांची के धुर्वा स्थित जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु जगन्नाथ अपने मुख्य मंदिर से निकल कर मौसीबाड़ी पहुंचे . भगवान जगन्नाथ जब रथ पर अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान होकर चले, तो उनका रथ खींचने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी. शाम पांच बजे के बाद भगवान का रथ खींचना शुरू हुआ. इस अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच विशेष उत्साह देखने को मिला . प्रभु जगन्नाथ शुक्रवार को अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर मौसी के घर पहुंचे. धुर्वा के जगन्नाथपुर स्थित मुख्य मंदिर से मौसीबाड़ी तक उनकी यह रथयात्रा बेहद मनभावक और दर्शनीय रही. बारिश नहीं होने के कारण भक्तों की भीड़ उम्मीद से ज्यादा थी. भक्तों की भीड़ का उत्साह और उमंग ऐसा था कि मुख्य मंदिर से महज 600 मीटर दूर स्थित मौसीबाड़ी पहुंचने में भगवान को करीब 02:35 घंटे का समय लग गया. श्रद्धा व आस्था से ओतप्रोत भक्तों ने महाप्रभु का जयघोष करते हुए उनका रथ खींचा और उन्हें भाई-बहन संग मौसीबाड़ी तक पहुंचाया.

शाम 5 बजे शुरू हुई रथ यात्रा

बता दें कि मुख्य मंदिर से भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के विग्रहों को रथ पर विराजमान करने के बाद शाम 05:00 बजे के करीब रथयात्रा का शुभारंभ हुआ. महाप्रभु का रथ खींचने की होड़ ऐसी थी कि भीड़ में शामिल ज्यादातर भक्तों के हाथ रथ के रस्सी तक नहीं पहुंच पा रहे थे. सभी भक्त किसी तरह रथ की रस्सी पकड़ कर उसे खींचना चाह रहा था. इस प्रयास में सफल नहीं हो पानेवाले भक्त एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर ही उसे खींच रहे थे. वहीं, बड़ी संख्या में भक्त रथ को पीछे से धक्का दे रहे थे. कई बार रथ की रस्सी भी टूट गयी, जिसे दोबारा जोड़ कर रथ को खींचा गया.

इधर, सभी विग्रहों को रथ पर विराजमान करने के बाद उनका श्रृंगार किया गया. इसके बाद श्रीविष्णु लक्षार्चना किया गया और अर्चित पुष्प को मुख्य पुजारी ने जगन्नाथ स्वामी सहित अन्य के श्री चरणों पर समर्पित किया. इसके बाद आरती, जगन्नाथ अष्टकम का पाठ और रस्सा बंधन का विधान पूरा किया गया. पूजा-अर्चना में रामेश्वर पाढ़ी, रामेश्वर पाढ़ी, पं कौस्तुभधर नाथ मिश्रा, श्रीराम मोहंती, मदन पाढ़ी, विपिन उपाध्याय, अश्विनी नाथ मिश्रा, शशांकधर नाथ मिश्रा, समिति के प्रथम सेवक सेवायत ठाकुर सुधांशु नाथ शाहदेव के अलावा अन्य भक्त पूजा में

वहीं, रथयात्रा में हटिया विधायक नवीन जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, खिजरी विधायक राजेश कच्छप, वरीय कांग्रेस नेता विनय सिन्हा दीपू, पूर्व सांसद यदुनाथ पांडेय सहित अन्य शामिल हुए. रथ का संचालन हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्र कर रहे थे

शेखावाटी के संतों के सानिध्य में हैदराबाद में होगी भजन संध्या
पीसीसी चीफ लक्ष्मनगढ विधायक डोटासरा के आतिथ्य में होगा आयोजन

हैदराबाद 29 जुन शेखावाटी के संतों के सानिध्य में व पीसीसी चीफ लक्ष्मनगढ विधायक के आतिथ्य में हैदराबाद के भाग्यनगर में तृतीय विशाल संख्या का आयोजन होगा।

इस आशय का निर्णय श्री सालासर बालाजी नवयुवक मंडल हैदराबाद के अध्यक्ष महेश सैनी की अध्यक्षता में सैनी टावर में आयोजित मीटिंग में लिया गया। यह जानकारी देते हुए मंडल के सचिव विकास शर्मा ने बताया कि आयोजन की तैयारी को लेकर रविवार को आयोजित मीटिंग में निर्णय लिया कि 2 अगस्त को तृतीय विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शेखावाटी के सिद्ध संत कैलाशनाथ महाराज व युवा संत गुलाब नाथ महाराज के सानिध्य में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आतिथ्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन होगा। मीटिंग में मंडल के उपाध्यक्ष दामोदर तिवाड़ी, सम्पत पारीक, सहसचिव नंदुसिंह राजपुरोहित, कोषाध्यक्ष किशोर शर्मा,सह कोषाध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा,आनंद कुमार शर्मा , केदार शर्मा, ओम प्रकाश चौधरी, इंदरपाल सैनी, श्रवण पारीक ,मुरली शर्मा, ढगलाराम , केके बन्ना सहित मंडल के पदाधिकारी सदस्य मौजूद थे।

श्री बालाजी भक्त मंडल हैदराबाद की मीटिंग आयोजित

सैनिकपुरी स्थित हाई टेन्शनरोड़ साईंबाबा आंफिसर्स कॉलोनी R J 22 मिरचीवाले उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित प्रबंधक प्रकाश सीरवी, मांगीलाल सोलंकी, दिनेश (डुगाराम) विनोद, सीरवी समाज बालाजी नगर वडेर अध्यक्ष जयराम पंवार, सचिव हीरालाल चोयल, नारायण लाल बर्फा, घेवरराम चोयल , श्री आईजी गौशाला सचिव हुक्माराम सानपुरा,अचलाराम हाम्बड़, सोहनलाल , नरेश सोलंकी, वेनाराम चोयल, योगा मास्टर रमेश , आशीर्वाद प्रबंधक बाबूलाल काग , जगदीश मालवीया , नंदाराम गेहलोत , कालुराम गेहलोत , पप्पूराम गुजर राजु सोलंकी, सुरेश सोलंकी, हरीश, बी आर एस चैनल एवं राठौड़ साउंड बबलू , जगदीश सीरवी पत्रकार व अन्य।

चाईबासा के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में पारंपरिक 'छेरा पंहरा' के साथ रथयात्रा आरंभ

परिवहन विशेष, स्टेट हेड , झारखंड

रांची , झारखंड स्थित सिंहभूम जिला मुख्यतः हो एवं ओड़िया भाषियों का सदैब रहा है ।पुरी जगन्नाथ के रास्ते यहां आये राजाओं का शासन क्षेत्र रहा सिंहभूम । जगन्नाथ के परम आराध्य सेवक आदिम जनजाति सबर विश्वाबसु की तरह यह हो जनजातीय बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ ओड़िया भूईयां संप्रदाय लोग उन्हें राजा बनाए थे, यहां पुरी खोरधा की तरह तलवार वाज खंडायत जगन्नाथ सीमा सुरक्षा प्रहरी रहे उत्तर कलिंग मे ।अतीत मे इलाका यह उत्तर कलिंग रहा जहां के देवता प्रभू जगन्नाथ बहुत पहले से रहे हैं। रथ यात्रा तब भी यहां मुख्य त्याहार रहा ।आज भी याहां उत्कल के देवता जगत के नाथ की भव्य रथयात्रा का आयोजन सैकड़ों जगहों पर होती है । जहां हर जगह सैकड़ों की भीड़ व मेला एक आकर्षक दृश्य प्रस्तुत करते हैं जिसे- हर वर्ग- रथ परव कहते । रथयात्रा की विधिवत पूजा अर्चना चाईबासा के ऐतिहासिक मंदिर मे स्व देवनारायण मिश्र पुरोहित परिवार के सदस्य गण 1857 के बाद से करते आ रहे हैं जो पुरी जगन्नाथ से मन्नत व आदेश के बाद यहां पूजा भव्य रूप से अंग्रेज शासन काल से आरंभ की । जब इलाका ब्रीटिस इंडिया शासन तंत्र में जाकर विलकिंसन रूल अधीन शासित हुआ आज संविधान के पांचवीं अनुसूची में दर्ज है ।

इस वर्ष भी हर वर्ष की तरह रथयात्रा का आयोजन पूर्व ₹छेरा पंहरा₹ चाईबासा मंदिर में कार्तिक कुमार परिच्छा ने की । यद्यपि चाईबासा जिला से सटा क्योंझर राज्य के राजकुमार तब गोविंद भंज थे जो पुरी गजपति पुरूषोत्तम देव कार्यकाल 1468-1497

के कांची युद्ध में यही से जाकर खोर्ध में सेनापति रहे । कांची की इष्टदेवी मां विपत्ति तारिणी को पहले राजकुमारी पद्मावती के साथ कांची पुरी लाई गयी फिर गोविंद भंज ने उन्हें क्योंझर लाने के समय घट गांव में स्थायी रूप में आज भी है। जिनके लिए प्रतिदिन लाखों मन्नत के नारियल विभिन्न राज्यों से घट गांव आज भी आता है ।

दो दिन पूर्व रथयात्रा आरंभ के समय विधिवत पूजा अर्चना चाईबासा जगन्नाथ मंदिर में पंडित गणों ने जगन्नाथ , बलभद्र, शुभदा तथा आयुध सुदर्शन के साथ आरंभ हूई । जिसमें जगन्नाथ जी के आदेश के साथ उनपर चढ़े माला मिलने के साथ छेरा पंहरा कार्यक्रम आयोजित की गयी । जहां कार्तिक

कुमार परिच्छा ने रथ एवं उसके पथ पर गोबर, चंदन जल डाल कर शुद्ध किया ।यह रश्म आज भी पूरी में गजपति महाराज करते हैं जब पूर्व गजपति कपिलेन्द्र देव राउत राय के पुत्र पूरूषोत्तम देव को कांची के राजा शाल्य नरसिंह ने अपनी बेटी पद्मावती को उनके जगन्नाथ के लिए झाड़ू करते देख चांडाल कार्य करने वाले राजा के साथ बेटी ब्याह देने से इंकार कर दिया था कभी । पौराणिक , ऐतिहासिक कथा अनुसार जहां जगन्नाथ एवं बलभद्र दोनों भाई उक्त शादी में घोड़े पर सवार होकर गये थे ढाल तलवार पकड़ कर लड़ाईयां लड़े ।युद्ध जीतने के बाद पद्मावती को बंदी बनाकर लाये थे तथा उनकी शादी किसी चंडाल से कराने हेतु चंडाल वर खोजने को गजपति ने आदेश दिया ।वही उनके चतुर मंत्री विद्यापति ने स्वयं पुरूषोत्तम देव को ही श्रेष्ठ चंडाल कहकर उनके साथ पद्मावती को ही शादी करवादी थी । आज विदेशों में भी करीब 140 से अधिक देशों में जगन्नाथ जी की पूजा होती है जहां यही रश्म अदायगी हर जगह की जाती जबकि अतीत के सिंहभूम में कार्तिक परिच्छा का परिवार जगन्नाथ सीमा सुरक्षा प्रहरी उत्तर कलिंग का ₹ परिच्छा सेवक ₹ सैनिक परिवार रहा। वे उत्तर परिच्छा है जो यहां पवित्र रथयात्रा पर छेरा पहरा किरते आये है ।जहां सैकड़ों की संख्या में लोग , भक्त मौजूद थे ।हजारों की तादाद में भक्तों को अन्न व्यंजन प्रदान की गयी तथा रथारूढ जगन्नाथ को नगर भ्रमण के बाद गुडिचा मंदिर तक लेजाया गया ।

भारी बारिश से झारखंड में जन-जीवन प्रभावित, विधालय के 162 बच्चों ने ऊपरी मंजिल में बिताई रात

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड-झारखंड

रांची , झारखंड मे लगातार वर्षा जारी है प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के कारण सड़कों से लेकर स्कूल तक में पानी लबालब है ।वही दक्षिणी झारखंड के कुछ जिले ज्यादा ही प्रभावित हैं । लगातार हो रही बारिश के कारण एक आवासीय स्कूल में चारों तरफ पानी ही पानी भर गया तो रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन को आना पड़ा। इस स्कूल में फंसे 162 छात्रों को तब बाहर निकाला गया जब उन्होने जान बचाने हेतु ऊपर फ्लौर पर जाना पड़ा था।

पूर्वी सिंहभूम के कोवाली थाना क्षेत्र में शनिवार रात को हल्दीपोखर-कोवाली रोड पर स्थित पंडरसोली विद्यालय में चारों तरफ से पानी से घिर गया। पानी से घिर जाने के कारण बच्चे स्कूल में फंस गए। जब स्कूल डूबा तो विद्यालय प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्कूल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, तो प्रशासन ने बच्चों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सभी बच्चों को बारी-बारी से बाहर निकाल लिया गया।

इस घटना की जानकारी देते हुए एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि शनिवार रात को भारी बारिश के कारण स्कूल परिसर पानी से भर गया था । गर्ग ने बताया कि आज सुबह करीब 5 बजे सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम और दमकल की टीमें पहुंचीं। यहां गांव वालों की मदद से एक-एक कर छात्रों को बाहर निकाला गया। इस दौरान एनडीआरएफ की मदद भी लेनी पड़ी ।

यदि आपके पास हेलमेट नहीं है, तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा और आपको कड़ी सजा दी जाएगी

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भूबनेश्वर : नुआपड़ा जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं बस स्टैंड नोडल समिति की बैठक शनिवार को नुआपाड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुभाष चंद्र राउत ने की, तथा इसमें जिला मुख्य विकास अधिकारी लम्बादार धरुआ, उप जिला मजिस्ट्रेट जोगेंद्र माझी, सीडीएमओ डॉ.

मनोज कुमार साहू, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मान सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। सिविल इंजीनियरिंग विभाग के अधीक्षण अभियंता शशा शेखर शुक्ला ने आगामी माह के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ पिछली बैठक का ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में चर्चा के बाद कुछ निर्णय लिए गए। प्रत्येक रविवार और बुधवार को हेलमेट और यदि आपके पास हेलमेट नहीं है, तो आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसकी निगरानी सभी बीडीओ, तहसीलदार और आरटीओ करेंगे। नाबालिगों और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जाएगी। आरटीओ, पुलिस और आबकारी विभाग मिलकर वाहनों की जांच करेंगे। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा और इसके लिए सभी को जागरूक करना होगा। इसमें जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संगठनों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। इसके बाद जिले के परिवहन क्षेत्र और बस स्टैंड के सुधार के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। हमारी बसों का नया रूट चार्ट, नुआपाड़ा बस स्टैंड में दिन-रात चलने वाली सभी बसों का प्रवेश अनिवार्य करने, महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए महिला गार्ड की तैनाती, निजी बसों से प्रवेश शुल्क वसूलने आदि विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में सिनापाली ब्लॉक बीडीओ कर्मी ओराम, कोमना बीडीओ विनय कुमार भोई, डीएसपी रमाकांत जेना, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी विद्यापति पंडा, एमवीआई उपेंद्र कुमार पुसिका, पीडब्ल्यूडी विभाग के संयुक्त कार्यकारी अभियंता सुकांत कुमार गरडिया, एनएच इंजीनियर आशीष कुमार नायक प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

पुरी में प्रशासन की लापरवाही के कारण कई श्रद्धालु घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

पुरी/भूबनेश्वर : महाप्रभु की विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा के तीसरे दिन एक बड़ा हादसा हुआ। प्रशासन की लापरवाही के कारण कई श्रद्धालु घायल हो गए और 3 लोगों की मौत हो गई। जिसके लिए मुख्य रूप से पुलिस और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया गया है। घायलों का इलाज पुरी सदर मुख्य अस्पताल में चल रहा है, जबकि शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है।

श्रीगुंडिचा मंदिर के रथ की सामने दर्शन के दौरान अचानक भगदड़ हुआ, जिससे कुछ भक्त नीचे गिरकर घायल हो गयी और तीन लोगों की मौत हो गई। इस घटना के संबंध में एक वरिष्ठ सेवादार ने विस्फोटक बयान देते हुए कहा कि प्रशासन की अक्षमता दुर्घटना का मुख्य कारण है। मौजूदा रथ यात्रा में पहले की तुलना में अधिक लोग आए हैं। इसे पुलिस बल द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। लाखों लोग सुनहरे दर्शन में आ रहे हैं। लेकिन आज लोग दर्शन करने आए और एक जगह इकट्ठा हो गए। लेकिन पुलिस इसे नियंत्रित नहीं कर सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि भीड़ नियंत्रण के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण ऐसी घटना हुई। मृतकों में खोरधा के गोबरधनपुर इलाके की बसंती साहू (36), भुवनेश्वर के नयापल्ली इलाके के प्रेमकांत मोहंती (78) और बालीपटना इलाके की पार्वती दास शामिल हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार देर रात श्री विग्रह के रथ को देखने के लिए कई भक्त आए थे। हालांकि, चूंकि ठाकुर जुलूस में थे, इसलिए कई भक्त रथ के सामने सो रहे थे। दूसरी ओर, रथ में दो वाहन खड़े थे। हालांकि, सुबह करीब 4:20 बजे जुलूस खोला गया। इस समय, रथ को देखने वाले भक्त रथ की ओर दौड़े। जो लोग पहले से वहां थे, उन्होंने उठने की कोशिश की। हालांकि, भीड़ अधिक होने के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई। भगदड़

में कुछ लोग नीचे गिर गए। लोग उनके ऊपर चढ़ गए। इस बीच, लोगों ने शिकायत की कि घटना स्थल पर पुलिस और एम्बुलेंस नहीं थी। घायलों को उनके परिवारों द्वारा चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। हालांकि, बताया गया है कि वहां 3 लोगों की मौत हो गई है। जिला मजिस्ट्रेट सिद्धार्थ शंकर स्वैन का कहना है कि मची भगदड़ में तीन लोगों की मौत हो गई परिणामस्वरूप वहां भगदड़ मच गई, जिसमें 9 लोग घायल हो गए। घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की मौत हो गई, जबकि 6 घायलों की हालत स्थिर है। वहीं, पुरी एसपी विनीत अग्रवाल ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस तैनात है। घटना की जांच की जा रही है। हालांकि, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। लोग शांति और व्यवस्था के साथ दर्शन कर रहे हैं। हालांकि, सूचना मिलने के बाद पुलिस महानिदेशक वाई.बी. खुरानिया और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का आकलन किया। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह दुर्घटना सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुई, जब श्री जगन्नाथ का नंदीघोष रथ मंदिर पहुंचा। भीड़ में बेकाबू भगदड़ में कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिससे यह दुखद घटना हुई। घायलों को तुरंत पुरी जिला मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023